आज का विचार

आपके जीवन का हर दिन नया होता है बस उसे जीने का नजरिया अलग होना चाहिए।

दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2026 वर्ष 24, अंक 98, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

फिनलैंड की यूनिवर्सिटी से पंजाब की साझेदारी वैश्विक शिक्षण तकनीकों को पंजाब के क्लासरूम तक पहुंचाने में मददगार

फिनलैंड के साथ सहयोग के रचनात्मक परिणाम सामने आ रहे, पंजाब के क्लासरूम बेहतरीन, अधिक प्रभावी शिक्षा की ओर अग्रसरः भगवंत सिंह मान

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार और फिनलैंड की टुर्कू यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग से पंजाब के क्लासरूम में प्रत्यक्ष बदलाव दिखने लगे हैं, जिसने शिक्षण प्रथाओं को अधिक आनंदमय और व्यावहारिक बना दिया है और विद्यार्थियों के लिए सीखने का माहौल अधिक प्रभावशाली बन रहा है।

इस पहल के हिस्से के रूप में पढ़ाई-लिखाई रट्टे मारने के तरीकों से हटकर अब अधिक आनंदमय और सहभागितापूर्ण सीखने के माहौल की ओर बढ़ रही है। पंजाब की व्यापक शिक्षा क्रांति में शामिल यह कार्यक्रम स्थानीय क्लासरूम में वैश्विक विशेषज्ञता को शामिल करने पर केंद्रित है, जो एक संरचित ट्रेन-द-ट्रेनर्स मॉडल के माध्यम से पैमाने को निर्धारित करता है, जिसमें बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगभग 300 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी।।

फिनलैंड की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कुकुलो-मोइकोइनेन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर सेंटर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पहले से ही स्थानीय क्लासरूम के साथ वैश्विक शिक्षा विशेषज्ञता को एकीकृत करके शानदार परिणाम दे रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के माध्यम से शुरू की गई यह साझेदारी प्रारंभिक और बुनियादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को मजबूत करने के प्रयासों की ओर अग्रसर है। यह

अल्पकालिक हस्तक्षेप के रूप में नहीं बल्कि पंजाब की शिक्षा प्रणाली में बाल-केंद्रित और खेल-आधारित शिक्षा को शामिल करने के लिए दीर्घकालिक संस्थागत प्रयास के रूप में तैयार की गई है, जिसमें बेहतरीन शिक्षा प्रथाओं को भी शामिल किया गया है।

यह कार्यक्रम शिक्षकों को शोध-आधारित तरीकों से सुसज्जित करने पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये दृष्टिकोण पंजाब के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के अनुकूल हों। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण सत्र चंडीगढ़ और फिनलैंड के शहरों टुर्कू तथा राउमा दोनों जगह आयोजित किए गए, जिसमें शिक्षकों को कार्यशालाओं, मार्गदर्शन प्रथाओं और स्कूलों के दौरों के माध्यम से क्लासरूम की नई तकनीकों से अवगत करवाना शामिल है। गौरतलब है कि मई 2026 तक चार समूहों में लगभग 300 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, जिससे पूरे पंजाब भर के विद्यार्थियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देते हुए कहा, शिक्षा को आनंदमय और दिलचस्प बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए हम रट्टे लगाने के पुराने तरीकों के स्थान पर सक्रिय सहभागिता की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षकों को विशेषज्ञों की सहायता वाले संदर्भ-विशिष्ट प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है ताकि इन विचारों को उनके अपने क्लासरूम में लागू किया जा सके। क्षेत्र से मिले फीडबैक से विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रेरणा में सुधार होता है और क्लासरूम का वातावरण सकारात्मक बनता है।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विस्तृत बातचीत के लिए टुर्कू यूनिवर्सिटी और टुर्कू शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल का भी दौरा किया। उन्होंने कहा, सरकार अब कार्यक्रम को 'ट्रेन-द-ट्रेनर्स' दृष्टिकोण के माध्यम से विस्तारित करने की योजना बना रही है, जिससे प्रांत भर में इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स का एक कैडर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, निरंतर व्यावसायिक विकास और व्यापक पहुंच का समर्थन करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मिश्रित प्रशिक्षण फॉर्मेट भी विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, विस्तार के लिए एक संरचित प्रणाली और प्रशिक्षित शिक्षकों के बढ़ते पूल के साथ इस सहयोग को पंजाब के व्यापक शिक्षा सुधारों की नींव के रूप में देखा जा रहा है। प्रांत जन शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विद्यार्थी सफल होने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें और इस क्षेत्र में गति बनाए रखने के लिए इसी प्रकार की पहल की जाएंगी।

पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण, तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटों पर जबरदस्त मतदान

बंगाल में पहले चरण में तृणमूल और भाजपा दोनों ने किया अपनी-अपनी जीत का दावा

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली/ कोलकाता/चेन्नई

तमिलनाडु विधानसभा की सभी सीटों और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में गुरुवार को मतदाताओं का जबर्दस्त उत्साह सामने आया। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों के बावजूद सुबह 7 से शाम 6 बजे तक दोनों ही राज्यों के मतदाताओं ने पिछले आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 91.40 फीसदी और तमिलनाडु में 84.35 फीसदी मतदान हुआ। इस दौरान पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आईं जबकि तमिलनाडु में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मतगणना 4 मई को होगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज राज्यभर में कड़ी सुरक्षा और व्यापक प्रशासनिक निगरानी के बीच संपन्न हुआ। इस चरण में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कुल 1478 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद हो गया। सुबह से ही मतदान

केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं और पूरे दिन मतदान का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। खास बात यह है कि इस बार जबर्दस्त मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 91.40 प्रतिशत मतदान हुआ, जो पिछले चुनावों की तुलना में काफी अधिक है। इस चरण में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर जैसे जिलों में मतदान हुआ। ये सभी जिले भौगोलिक और सामाजिक रूप से विविधता वाले क्षेत्र हैं, जिनमें सीमावर्ती इलाके, चाय बागान क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी केंद्र भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार प्रथम चरण में लगभग 3.6 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे। कुल 44,376 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 5644 मतदान केंद्रों का संचालन महिलाकर्मियों द्वारा किया गया, जबकि 207 मतदान केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से यह चरण अबतक के सबसे सख्त इंतजामों में से एक माना जा रहा है। पूरे राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 2407 कंपनियां तैनात की गईं। संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, फ्लाइंग स्क्वॉड और विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई।

मतदान के दौरान अधिकांश सीटों पर भारी उत्साह देखने को मिला और कई जिलों में मतदान 90 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया। दक्षिण दिनाजपुर सबसे आगे रहा, जहां 93.12 प्रतिशत मतदान हुआ। केवल कालिम्पोंग ऐसा जिला रहा जहां मतदान 81.98 प्रतिशत रहा।

हालांकि, पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ हिस्सों में छिटपुट हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगा, जबकि बीरभूम के लाभपुर में भाजपा एजेंट के घायल होने की घटना सामने आई। इसी जिले के खैराशोल में ईवीएम खराबी के बाद मतदान रुका, जिसके बाद पथराव और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की खबरें आईं, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी का सिर फट गया।

प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी ने किया स्थलीय निरीक्षण

एजेंसी (हि.स.)

हरदोई

उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में 29 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के आगमन एवं गंगा एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिलग्राम तहसील के मल्लावां कट स्थित कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड, सभा स्थल, वीआईपी मार्ग, पार्किंग, बैरिकेडिंग, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सहित सभी तैयारियों का गहनता से जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरी तरह सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गरिमामयी ढंग से संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहे और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मल्टी-लेयर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सभा स्थल का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने बैठने की समुचित व्यवस्था, पंडाल की गुणवत्ता, पेयजल उपलब्धता, स्वच्छता, शौचालय और निर्बाध विद्युत आपूर्ति को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हों। यातायात प्रबंधन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि कार्यक्रम के समय ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनी रहे। इसके लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और स्पष्ट संकेतक (साइन बोर्ड) लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो।

कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित करें अधिकारी

मुख्यमंत्री ने हेलीपैड और वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आपातकालीन सेवाओं-एम्बुलेंस, अग्निशमन और चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाए और जहां भी कमी हो, उसे तुरंत दूर किया जाए। इस अवसर पर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने मानचित्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और आश्वस्त किया कि सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल और आसपास हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ह्यहरि शंकरीह्ण प्रजाति के पौधों के रोपण के निर्देश भी दिए। अंत में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जनपद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी, समन्वय और समर्पण के साथ कार्य करते हुए इसका सफल और गरिमामय आयोजन सुनिश्चित करें।

वर्षों के अनुशासित प्रयासों और त्याग की परिणति है दीक्षांत समारोहः उपराष्ट्रपति

एजेंसी (हि.स.)

ऋषिकेश

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि दीक्षांत समारोह न केवल वर्षों के अनुशासित प्रयासों और त्याग की परिणति है, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरूआत भी है। उन्होंने स्नातकों से समर्पण और उद्देश्य की भावना के साथ अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभाने का आग्रह किया।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन गुरुवार को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं को पदक और उपाधियां वितरित कीं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह न केवल वर्षों के अनुशासित प्रयासों और त्याग की परिणति है, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरूआत भी है। उन्होंने स्नातकों से समर्पण और उद्देश्य की भावना के साथ अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभाने का आग्रह किया। उन्होंने ऋषिकेश को चिंतन और उपचार का वैश्विक केंद्र और हिमालय का प्रवेश द्वार बताते हुए उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसा वातावरण दीक्षांत समारोह की गंभीरता को और भी गहरा कर देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सतत नवाचार और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारत के व्यापक टीकाकरण अभियान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 14 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त टीके लगाए गए, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए टीके विकसित किए हैं।

ईंधन और खाद्य सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार विफल : कांग्रेस अध्यक्ष

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर ईंधन और खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर विफलताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी नाकामियों और गंभीर आरोपों से ध्यान हटाने के लिए सीमांकन (डिलिमिटेशन) का सहारा लिया लेकिन देश ने इस दिखावे को समझ लिया।

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि भारत का कच्चे तेल का उत्पादन लगातार 11वें वर्ष गिरावट पर है और 2014-15 से अब तक कुल उत्पादन में लगभग 22 प्रतिशत की कमी आई है। गैस उत्पादन में भी लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग के लिए लंबी प्रतीक्षा और कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि ईंधन संकट के साथ ही

उन्होंने कहा कि भारतीय जहाजों को होरमुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित मार्ग नहीं मिल रहा है और 14 भारतीय ध्वज वाले जहाज 54 दिनों से वहीं फंसे हुए हैं। खरगे ने कहा कि मार्च 2026 में खाद उत्पादन पांच साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है और इसमें 24.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। चीन ने जुलाई 2025 में विशेष खादों पर प्रतिबंध लगाया था और रूस ने भी निर्यात रोक दिया है लेकिन मोदी सरकार ने आयात विविधीकरण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को लगातार खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है और यह सरकार की उदासीनता का परिणाम है।

सुजुकी के सीईओ का सीएम नायब सैनी से वायदा- भविष्य में हरियाणा में और भी निवेश करेगी सुजुकी

भूपेंद्र शर्मा

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सुजुकी मोटर के सीईओ तोशीहिरो सुजुकी ने मुलाकात की। इस दौरान सीईओ तोशीहिरो सुजुकी ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से वायदा किया कि सुजुकी मोटर भविष्य में भी हरियाणा के अंदर और निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि भारत की प्रोग्रेस के साथ-साथ हरियाणा की प्रोग्रेस में भी उनकी कंपनी पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए जापान में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने 20 जून को टोक्यो विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में आने के लिए सुजुकी के सीईओ तोशीहिरो सुजुकी को न्यौता भी दिया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा पहले भी सुजुकी मोटर को सहयोग करता रहा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में सुजुकी मोटर हरियाणा में ही निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि सुजुकी मोटर इकलौती ऐसी कंपनी है जिसे हरियाणा राज्य ने एसजीएसटी इनसेंटिव दिया है। इस पर सीईओ तोशीहिरो सुजुकी ने कहा कि वह भारत में हाईब्रिड और सीएनजी गाड़ियों पर फोकस करेंगे। भविष्य में यदि उन्हें ईवी के लिए गाड़ियां बनानी पड़ी और नया प्लांट बनाया तो निश्चित रूप से निवेश के लिए उनकी पहल हरियाणा होगा। उन्होंने कहा कि सुजुकी के साथ हरियाणा सरकार का कम्यूनिकेशन ऐसे ही बना रहे और हरियाणा सरकार का सहयोग मिलता रहे। उन्होंने कहा कि 1982-83 में सुजुकी को शुरू किया था, तब हमने पाया कि

भारत और जापान के काम करने का तरीका अलग है लेकिन फिर भी भारत और जापान में बहुत सारी समानता है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए जून महीने में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन जापान में किया जाएगा। उन्होंने सुजुकी के सीईओ से अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के दिव्य आयोजन में जापानी नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को जापान के किसी प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन के साथ जोड़ने में सहयोग करने का आग्रह किया। इस पर सीईओ तोशीहिरो ने विचार करने पर हामी भरी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सीईओ सुजुकी को 20 जून को टोक्यो विश्वविद्यालय में आयोजित एक 'अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार' में बतौर विशिष्ट अतिथि आने का न्यौता भी दिया। इस पर सीईओ सुजुकी ने कहा कि वह पवित्र ग्रंथ गीता को पढ़ेंगे और इस सेमिनार में शामिल होने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र और जापान के बीच सिस्टर सिटी का एमओयू करने का आग्रह भी सीईओ तोशीहिरो सुजुकी के समक्ष रखा। उन्होंने इसमें सहयोग करने का आश्वासन दिया।

सुजुकी मोटर के सीईओ तोशीहिरो सुजुकी ने कहा कि कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसमें और अधिक निवेश करने की योजना है। अभी 9 बायोगैस प्लांट लगाने की योजना है। इनमें से 2 बायोगैस प्लांट लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खरखौदा प्लांट में सुजुकी स्ट्रॉग हाईब्रिड गाड़ियां का निर्माण करेगी। इसकी प्रोडक्शन और सेल में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार से सहयोग मांगा। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सहयोग देने का आश्वासन दिया। सीईओ तोशीहिरो सुजुकी ने कहा कि नई औद्योगिक पॉलिसी-2026 में स्ट्रॉग हाईब्रिड और सीएनजी गाड़ियों के संबंध में भी कोई न कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने शहरों को इस तरह से बसाना चाहिए कि आने वाले 10 या 20 साल बाद उनकी स्थिति अच्छी हो, अच्छी सुविधाएं हों।

बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक इंडस्ट्रीज श्री यश गर्ग, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर श्री राजीव जेठली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एटीएस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिले वाहन आपरेटर्स को मिला मैनुअल फिटनेस टेस्ट का आश्वासन

एटीएस की अनिवार्यता को लेकर चल रहे विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम

परिवहन संघों ने मुख्यमंत्री के फैसले का किया स्वागत

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) मामले को लेकर बस, टैक्सी एवं ट्रक ओपेरेटर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांगड़ा एयरपोर्ट पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष एटीएस के मुद्दे को उठाते हुए उन्हें राहत देने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने इस मामले में ओपेरेटर्स को आश्वस्त किया कि फिलहाल उनकी समस्या को देखते हुए कांगड़ा जिला में मैनुअल फिटनेस प्रक्रिया को भी जारी रखा जाएगा जिस पर प्रतिनिधिमंडल ने उनका

आभार जताया। वहीं इस मौके पर उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने ओपेरेटर्स की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया है कि कांगड़ा जिले में आरटीओ तथा एमवीआई के माध्यम से भी फिलहाल कमर्शियल वाहनों के लिए मैनुअल फिटनेस टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पहाड़ी राज्यों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों से भी आग्रह किया कि वे ऑपरेटर्स की समस्याओं को देखते हुए इस मुद्दे की पैरवी केंद्र सरकार के समक्ष करें। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा वाहनों की फिटनेस जांच को

मुख्यमंत्री ने की यूटिलिटी डक्ट के निर्माण कार्य की समीक्षा

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निमार्णाधीन यूटिलिटी डक्ट के ऊपर तारकोल बिछाने का कार्य शिमला क्लब तक 10 मई और लिफ्ट तक 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके।उन्होंने कहा कि शिमला शहर में छोटा शिमला से विलीज पार्क तक सात किलोमीटर लंबे यूटिलिटी डक्ट के निर्माण पर 145 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने विभाग को कार्य में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा में इसे पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला न केवल राज्य की राजधानी है बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। उन्होंने कहा कि शहर को पेड़ों पर लटके तारों के जाल से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और इसकी सुंदरता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।यह यूटिलिटी डक्ट छोटा शिमला से विलीज पार्क, सचिवालय होते हुए लोक भवन से ओक ओवर तक तथा शेर-ए-पंजाब से लोअर बाजार होते हुए सीटीओ और विलीज पार्क तक विस्तारित होगा

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के माध्यम से अनिवार्य किया गया है, जिससे प्रदेश में कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं।इस अवसर पर कांगड़ा जिला की विभिन्न ओपेरेटर्स यूनियनों के पदाधिकारियों में विक्की पठानिया, करतार पठानिया, मेहर सिंह ठाकुर, मोहिंदर सिंह, संजय शर्मा, कार्तिक शर्मा, कुलजीत राणा, नीका राम, कर्मा, अशोक शर्मा तथा कपिल उपस्थित रहे।

पहले फैसले लो फिर पलटो, यही बन गई कांग्रेस सरकार की पहचान : बिक्रम ठाकुर

जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करने का दावा

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में शासन का स्तर इतना गिर चुका है कि सरकार खुद ही अपने फैसलों की विश्वसनीयता खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले निर्णय, फिर यू-टर्न की नीति पर चल रही है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह मजाक बना दिया है।

वीरवार को जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में सरकार द्वारा लिए गए अनेक फैसले ऐसे हैं जिन्हें जनता के विरोध के बाद तुरंत वापस लेना पड़ा। चाहे बिजली सब्सिडी खत्म करने का मामला हो, बाहरी राज्यों के वाहनों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला हो, कर्मचारियों के वेतन और पदों को लेकर निर्णय हों या सरकारी संपत्तियों के किराए में भारी बढ़ोतरी, हर मुद्दे पर सरकार पहले जनता पर बोझ डालती है और फिर दबाव में आकर पीछे हट जाती है। यह स्थिति दशार्ती है कि सरकार के पास न कोई स्पष्ट नीति है और न ही दूरदर्शिता। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व पूरी तरह कमजोर साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री बिना किसी ठोस योजना या आंकड़ों के फैसले लेते हैं, जिससे प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बनता है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस भ्रम में हैं कि कौन सा निर्णय स्थायी है और कौन सा कुछ ही दिनों में पलट जाएगा। बिक्रम ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वह अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। बार-बार एक ही प्रकार की गलतियां दोहराई जा रही हैं, जिससे साफ है कि सरकार के पास न तो नीति-निर्माण की क्षमता है और न ही प्रशासनिक नियंत्रण। उन्होंने कहा कि जनता अब कांग्रेस के इस यू-टर्न मॉडल को पूरी तरह समझ चुकी है। प्रदेश की जनता स्थिरता, पारदर्शिता और विकास चाहती है, लेकिन कांग्रेस सरकार इन तीनों मोर्चों पर पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के फैसलों ने निवेश के माहौल को भी प्रभावित किया है, जिससे रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और युवा निराश हो रहे हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस असफल और दिशाहीन सरकार को आने वाले समय में करारा जवाब देगी।

आदतन नशा तस्कर को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में भेजा जेल

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

जिला शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आदतन नशा तस्कर को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो लोग बार-बार नशे के कारोबार में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ अब निरोधात्मक कार्रवाई सख्ती से की जा रही है, ताकि उन्हें समाज और सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रखा जा सके।

इस कार्रवाई के तहत खेमराज उर्फ सनी वालिया, निवासी गांव व डाकघर बसंतपुर, तहसील व थाना सुन्नी, जिला शिमला को हिरासत में लिया गया है। आरोपी की उम्र 40 वर्ष बताई गई है और उसे 21 अप्रैल को बसंतपुर क्षेत्र से पुलिस टीम ने डिटेन किया। यह कार्रवाई थाना सुन्नी पुलिस और जिला शिमला की डीसीआरबी टीम के सहयोग से की गई। इसके बाद आरोपी को 22 अप्रैल को आदर्श कारागार कंडा में दाखिल कर दिया गया।पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के तहत निरोधात्मक डिटेंशन आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए थे। इसी आदेश के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार खेमराज उर्फ सनी वालिया लंबे समय से नशा तस्करी के मामलों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मामले दर्ज हैं। इनमें थाना सुन्नी और बालूगंज थाने में पांच एफआईआर दर्ज हैं। इन सभी मामलों में आरोपी पर नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े आरोप दर्ज हैं।

कठुआ में आज रात सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, प्रशासन की लोगों से न घबराने की अपील

कठुआ। उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत जिला प्रशासन कठुआ आज 24 अप्रैल 2026 को रात 08:30 बजे पूरे जिले में सिविल डिफेंस एयर रेड/ब्लैकआउट मॉक अभ्यास आयोजित करेगा। यह अभ्यास सभी लाइन विभागों और संबंधित एजेंसियों के समन्वय से किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आपात स्थितियों में तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत बनाना है।आदेश में बताया गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसे मॉक अभ्यास हर वर्ष अप्रैल और नवंबर माह में आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में अप्रैल माह का यह अभ्यास आज जिलेभर में कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट से बचें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें, ताकि अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। साथ ही सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यह मॉक ड्रिल निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया और एक्शन प्लान के अनुसार सख्ती से लागू की जाए।

कांग्रेस अध्यक्ष की प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफः सिकंदर कुमार

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे राजनीति के गिरते स्तर का उदाहरण बताया और कहा कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मयार्दाओं के खिलाफ है।

प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने गुरूवार को शिमला से जारी अपने बयान में कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना न केवल उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह देश की जनता का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय नेता हैं और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनके मुताबिक, कांग्रेस पार्टी बार-बार व्यक्तिगत टिप्पणियों के जरिए राजनीतिक बहस को भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा पहले भी इस तरह की टिप्पणियां की जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि साल 2007 में सोनिया गांधी द्वारा मौत का सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि 2017 में मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमीजैसी टिप्पणी की थी। इसके अलावा राहुल गांधी द्वारा कमांडर-इन-थीफ और प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं द्वारा भी विभिन्न मौकों पर विवादित बयान दिए जाने का जिक्र उन्होंने किया।सिकंदर कुमार ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक संवाद का स्तर गिरता है और इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। उनके अनुसार, लोकतंत्र में असहमति और आलोचना जरूरी है, लेकिन उसकी भाषा मर्यादित और गरिमापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों को मुद्दों पर बात करनी चाहिए। उनके मुताबिक जनता इस तरह की टिप्पणियों को गंभीरता से देखती है और चुनाव में इसका जवाब भी देती है।

संक्षिप्त-समाचार

नीट-2026 की तैयारियों की समीक्षा, कठुआ में पुख्ता सुरक्षा व सुचारु व्यवस्था के निर्देश

कठुआ। डीसी कठुआ राजेश शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को डीसी कार्यालय परिसर में नीट-2026 परीक्षा के सुचारु आयोजन को लेकर एक तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में 3 मई 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए लॉजिस्टिक्स, स्टाफ तैनाती और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जानकारी दी गई कि जिले में दो परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (बॉयज) कठुआ और आर्मी पब्लिक स्कूल जंगलोट में स्थापित किए गए हैं, जहां क्रमशः 600 और 566 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा स्टाफ की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, तथा परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और पारदर्शिता व अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि परीक्षार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि परीक्षा निष्पक्ष व व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विशवजीत सिंह, डीएसपी रविंदर सिंह, केंद्रीय विद्यालय जंगलोट के प्राचार्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

चेक बाउंस के दो मामलों में फरार आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

शिमला। शिमला जिले में वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रोहड़ू पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। पुलिस ने साल 2024 के दो मामलों में फरार चल रहे आरोपी कपिल देव उर्फ कपिल थोप्टा को गिरफ्तार किया है। वह रोहड़ू क्षेत्र के गांव शल्लान का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़े दो अलग-अलग मामले दर्ज थे, जिनमें उस पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई चल रही थी। इन मामलों में अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे, क्योंकि वह लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहा था। जांच में सामने आया था कि आरोपी ने अपनी वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए जो चेक जारी किए थे, वे बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि या अन्य कारणों से बाउंस हो गए थे। इसी वजह से दोनों मामले अदालत में लंबित थे। रोहड़ू पुलिस ने आरोपी की तलाश में लगातार अभियान चलाया और सुनियोजित कार्रवाई के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंटों की तामील भी सुनिश्चित की। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी।

जन आक्रोश महिला पदयात्राः भाजपा ने महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा

शिमला। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से गुरूवार को जन आक्रोश महिला पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने महिला आरक्षण और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए और अपनी बात रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सह प्रभारी संजय टंडन सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने नारेबाजी की और अपने मुद्दों को सामने रखा। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में एक अहम कदम था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं के मुद्दों पर गंभीरता से काम न करने का आरोप लगाया। डेजी ठाकुर ने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस विषय पर सभी दलों को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मि धर सूद ने कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है और इस पर विरोध करना सही नहीं है। भाजपा विधायक रीना कश्यप ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रही कुछ महिलाओं को रास्ते में रोका गया और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसे प्रशासनिक स्तर पर की गई कार्रवाई बताया। हालांकि, इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

भदरोई में भूमि पूजन के साथ 19.43 लाख की योजना का शुभारंभ

मंडी। कांग्रेस कमेटी के महासचिव पवन ठाकुर ने भदरोई में बीपीएमयू सरकाघाट के अंतर्गत आने वाली उप-परियोजना एफआईएस भदरोई में 430 मीटर लंबे फार्म एक्सेस रोड के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर विधिवत शुभारंभ किया। इस सड़क के लिए कुल 19,43,176 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पवन ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि फार्म एक्सेस रोड के निर्माण से किसानों को अपने खेतों तक सुगम पहुंच उपलब्ध होगी, जिससे कृषि कार्यों में तेजी आएगी और समय व श्रम की बचत होगी। यह पहल क्षेत्र की कृषि उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर बेसिक इंजीनियरिंग स्किल्स कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को निर्माण कार्यों से जुड़ी मूलभूत तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही किसानों को जाईका की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार से अवगत करवाया गया। किसानों को सोलर फेंसिंग, फार्म मशीनरी और हल्दी (टर्मरिक) की खेती जैसी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई।

कांग्रेस ने महिला आरक्षण पर किया विश्वासघात लोकतंत्र के लिए काला दिन : डेजी ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। शिमला में गुरुवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा हालिया घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है और इसे इसी रूप में याद किया जाएगा।

डेजी ठाकुर ने कहा कि यह एक ऐसा मौका था, जिसे ऐतिहासिक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि इससे महिलाओं को नीति निर्माण में भागीदारी का अधिकार मजबूत होता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इस अवसर को रोककर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। उनके मुताबिक, सितंबर 2023 में पारित हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता खुला था, लेकिन इस विषय पर विपक्ष ने गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर जिस तरह का माहौल बना और विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई, उसने उनकी सोच को उजागर कर दिया। उनके अनुसार, जब देश की महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा सामने था, तब विपक्ष का रवैया निराशाजनक रहा। डेजी ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है और जब अधिकार देने की बात आती है तो उन्हें पीछे कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है और वहां आम महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर कम मिलते हैं। इसके उलट उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनसे महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। डेजी ठाकुर ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में जन आक्रोश महिला पदयात्राह्व शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल विरोध नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए एक व्यापक अभियान है।

गोखड़ा में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन

मंडी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, गोखड़ा में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय, पर्यावरण चेतना तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं पृथ्वी दिवस चित्रकला प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा जसवाल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ प्रवक्ता राजेश नंदा को सौंपी गई थी। वाद-विवाद प्रतियोगिता के परिणाम प्रथम स्थान पर कनिका कक्षा +1, विवेकानंद हाउस , द्वितीय स्थान एकता कक्षा +1, कल्पना चावला हाउस, तृतीय स्थान पर संजना कक्षा +2, रामानुजम हाउस रही। उसी प्रकार निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हर्षिता एवं निखिता कक्षा 12वीं, द्वितीय स्थान पलक शर्मा 11वीं, मानसी 12वीं, मोहित (12वीं), तृतीय स्थान :निशा 12वीं, दीपाली 12वीं, पृथ्वी दिवस चित्रकला प्रतियोगिता पृथ्वी संरक्षण विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का सशक्त एवं प्रेरणादायक संदेश प्रस्तुत किया।

कठुआ में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई मेडिकल दुकानों व कूरियर सेवाओं पर कड़ी निगरानी

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत जिला प्रशासन कठुआ और कठुआ पुलिस ने गुरूवार को जिले भर में मेडिकल दुकानों और कूरियर सेवा केंद्रों पर व्यापक संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य नशीले एवं मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी पर रोक लगाना और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना रहा।

यह अभियान अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ विशवजीत सिंह के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें डीएसपी मुख्यालय रविंदर सिंह, सहायक औषधि नियंत्रक कठुआ तथा आरटीओ कार्यालय के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान दवाइयों की बिक्री और वितरण से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। विशेष रूप से नियंत्रित और शेड्यूल्ड दवाओं पर फोकस रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि किसी प्रकार की अनियमितता न हो। इसके साथ ही कूरियर सेवा केंद्रों पर आने-जाने वाले पार्सलों की अचानक जांच भी की गई, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या प्रतिबंधित पदार्थों की आवाजाही का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने कूरियर संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने और पार्सलों की जांच में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि में संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान संबंधित हितधारकों को जागरूक भी किया गया और उनसे अपील की गई कि वे नशे के खिलाफ इस मुहिम में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि समाज को इस गंभीर समस्या से मुक्त कराया जा सके।

जनगणना 2027 की तैयारी तेज, कठुआ में फील्ड ट्रेनर्स के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

डीसी कठुआ एवं प्रधान जनगणना अधिकारी राजेश शर्मा ने वीरवार को डीसी कार्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जनगणना 2027 (फेज-1 हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस) के तहत फील्ड ट्रेनर्स के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

अपने संबोधन में उपायुक्त ने जनगणना को सटीक योजना निर्माण और सुशासन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए प्रतिभागियों से पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ प्रशिक्षण लेने की अपील की, ताकि आंकड़ों की सटीकता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके। प्रशिक्षण सत्र जिला सांख्यिकी एवं मूल्यांकन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद और जनगणना संचालन निदेशालय, जम्मू-कश्मीर के मास्टर ट्रेनर संजय कुमार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें डिजिटल डेटा संग्रहण, जनगणना पद्धति और फील्ड स्तर के कार्यों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के नामित फील्ड ट्रेनर्स भाग ले रहे हैं, जो आगे जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। वहीं बिलावर और बसोहली के अतिरिक्त उपायुक्त तथा हीरानगर और बनी के एसडीएम वर्चुअल माध्यम से जुड़े। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा, जिसका उद्देश्य जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए फील्ड ट्रेनर्स की क्षमता को मजबूत करना है।

मौसम | **भीषण गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत, अलर्ट जारी**

हिमाचल प्रदेश में छह दिन बरसेंगे बादल, सतर्क रहने की सलाह

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में लगातार साफ मौसम के चलते गर्मी का असर तेज होता जा रहा है, लेकिन अब लोगों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को भी प्रदेश भर में तेज धूप खिली है। इससे दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊना सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है और राज्य का औसत न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री ज्यादा चल रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार 24 अप्रैल से मौसम करवट लेने वाला है और कुछ स्थानों पर हल्की गतिविधियां (आइसोलेटेड) शुरू हो सकती हैं। 25 अप्रैल को कई जगहों पर बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 26 और 27 अप्रैल को भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश और गर्जना की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। 28 और 29 अप्रैल को मौसम और सक्रिय होगा, जब कई इलाकों में बादल छाने, गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 25, 27, 28 और 29 अप्रैल के लिए गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि इन छह दिनों के दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम में इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी हवा के चक्रवातीय सिस्टम को माना जा रहा है, जो क्षेत्र में सक्रिय होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में कमी और मौसम के सुहावना होने की उम्मीद है, जिससे प्रदेशवासियों को तपती गर्मी से काफी हद तक राहत मिल सकती है। इस बीच, राज्य में दिन के साथ रातें भी गर्म हो गई हैं और न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुकुमसेरी 5.1 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि इसके बाद ताबो 6.4, कल्पा 9.0, मनाली 10.4, सराहन 10.6, भुंतर 13.1, बरठीं 13.8, सोलन 15.0, सुंदरनगर 15.6, शिमला 16.4, पालमपुर 16.5, मंडी 16.7, धर्मशाला और ऊना 17.0-17.0, बिलासपुर 17.5, नाहन 18.0, कांगड़ा 18.2, जुब्बड़हट्टी 19.5, पांवटा साहिब और देहरा गोपीपुर 22-22 डिग्री दर्ज किए गए। इन आंकड़ों से साफ है कि रात का तापमान भी लगातार ऊपर जा रहा है, जिससे गर्मी का असर और बढ़ रहा है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा, स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।

संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

हरियाणा बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर का ग्लोबल हब, कंपनियां करेंगी भारी निवेश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की नायब सरकार राज्य को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम), आईटी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सरकार ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार कर रही है, जो इन उभरते क्षेत्रों में निवेशकों के लिए अत्यंत आकर्षक होने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, इनोवेशन और अत्याधुनिक तकनीकी विकास को भी गति देगी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को नई दिल्ली में नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी के संबंध में उद्योगपतियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि आईटी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और ईएसडीएम सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर रहा है। हरियाणा, अपनी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री-फ्रेंडली माहौल के चलते इस सेक्टर में वैश्विक निवेश आकर्षित करने की अपार संभावनाएं रखता है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को ग्लोबल कंपनियों का प्रमुख केंद्र बनाया जाए, जहां देश-विदेश की अग्रणी कंपनियां निवेश करें। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ईएसडीएम कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसमें कैपिटल सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट्स, स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे, ताकि उद्योगों को स्थापित करने और विस्तार करने में किसी प्रकार की बाधा न आए।

प्रतिनिधियों ने सुझाव देते हुए कहा कि फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट और कुछ कंपनियों का चयन करके उन्हें ग्लोबल कंपनी बनाने में मदद की जाए जिससे उस उद्योग से जुड़ी छोटी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा, स्टार्टअपस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी विशेष फोकस किया जाए और रिसर्च के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएं।

एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए विदेशों में प्रोडक्ट स्टोरेज की दिक्कतों के समाधान के लिए ग्लोबल वेयरहाउस स्थापित किए जाएं ताकि विभिन्न कंपनियां इन ग्लोबल वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट्स स्टोर कर सकें। बैठक के दौरान स्किल वर्कफोर्स की उपलब्धता के लिए कई कंपनियों ने आईटीआई एडॉप्ट करने की रुचि व्यक्त की जिससे कंपनियों को उनकी जरूरत के अनुसार मैनपावर मिल सकेगी।

माइक्रोसॉफ्ट से संदीप अरोड़ा ने युवाओं को भविष्य की उभरती तकनीकों के अनुरूप सक्षम बनाने के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्कूलों, आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (अक) आधारित स्टडी को बढ़ावा देने पर चर्चा की। इस पहल के तहत छात्रों को शुरूआती स्तर से ही एआई, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक स्किल्स से लैस किया जाएगा, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीतिगत समर्थन और इंसेंटिव्स प्रदान किए जाएंगे, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स (एवीजीसी-एक्सआर) सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार अलग से एक समर्पित सेक्टर पॉलिसी लाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे इस उभरते हुए क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग को संरचित विकास का प्लेटफॉर्म मिल सके। इस दौरान चेयरमैन, फिक्की एवीजीसी-एक्सआर फोरम श्री आशीष कुलकर्णी, डायरेक्टर, पब्लिक पॉलिसी, ई गेमिंग फेडरेशन देवभूति बख्शी, सीईओ मीडिया एंड स्किल एंटरटेनमेंट काउंसिल मोहित सोनी ने सुझाव दिया कि ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि युवाओं को नए अवसर मिलें और राज्य इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर सके। क्रिएटिव और परफॉर्मिंग स्किल्स के विकास के लिए इनक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे नवाचार, स्टार्टअप्स और टैलेंट को पोषण मिल सके तथा एवीजीसी-एक्सआर सेक्टर में हरियाणा को एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित किया जा सके।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंजौर स्थित ऐतिहासिक यादवेंद्र गार्डन में वेडिंग सिटी विकसित करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, और इसे राज्य के प्रमुख डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में स्थापित किया जा सकता है। आईएचसीएल) के प्रतिनिधि पुनीत मक्कड़ ने जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट को विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए ताज ग्रुप के साथ विस्तृत चर्चा चल रही है। इस साझेदारी के माध्यम से यह परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी। इसके अलावा, बैठक में फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज और ई वेस्ट सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ भी विस्तार से संवाद किया गया और उनके सुझाव लिए गए।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, निदेशक श्री यश गर्ग, अतिरिक्त निदेशक, सिविल एविएशन श्री मनीष कुमार लोहान, सीईओ एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गुरमीत सिंह, हेड पब्लिक पॉलिसी एंड डिजिटल इंफ्रा माइक्रोसॉफ्ट श्री संदीप, हेड कॉरपोरेट अफेयर्स इंडिया एंड पब्लिक पॉलिसी टीसीएस श्री रोहित चौहान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड श्री जगमोहन सूद, सीएमडी प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स श्री अशोक कनोडिया, वाईएसएम जाइरॉक्स एवियशन प्राइवेट लिमिटेड ब्रिगेडियर हितेन, एमडी एवं सीईओ ओस्टिक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड डॉ विनय सैनी सहित विभिन्न इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडू में भाजपा भारी बहुमत से बनाएगी सरकार : विज

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडू में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है जिसको लेकर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दोनों राज्यों में भाजपा की जीत का दावा किया और कहा कि दोनों राज्यों में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। श्री विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

पहलगाम में हुई आतंकी घटना को पूरा साल हो गया है जिस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो हमारा कायर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है ये निहत्थों पर छिपकर वार करता है, धर्म जाति पूछकर कत्ल करवाता है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वो राज चले गए जब श्रद्धांजलियां देकर घरों में बैठ जाया करते थे। अब ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने पाकिस्तान के दांत तोड़ दिए और उसको सबक सिखा दिया है, अब ये सहने वाला भारत नहीं है बल्कि समझाने वाला भारत है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया कि हम सब आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे जिस पर मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी सुबह कुछ है, शाम को कुछ है, आज कुछ है और कल कुछ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर अपने ही बयान निकाल कर देख लें तो उन्हें समझ आ जाएगा।

म्हारी सड़क एप : जनभागीदारी से बदल रही हरियाणा में सड़कों की तस्वीर

- सिटीजन फीडबैक आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म से बढ़ी पारदर्शिता और जवाबदेही
- 63,170 किमी सड़कों के निर्माण व मरम्मत का लक्ष्य, कार्यों में लाई जा रही तेजी
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं कर रहे एप पर शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में शुरू की गई म्हारी सड़क एप एक प्रभावी डिजिटल पहल के रूप में स्थापित हो रही है। इसके माध्यम से आम नागरिकों को सीधे शासन व्यवस्था से जोड़ते हुए सड़कों की स्थिति सुधारने में जनभागीदारी को सशक्त किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा विकसित यह एप नागरिकों के फीडबैक पर आधारित है, जिसके माध्यम से सड़कों से संबंधित शिकायतों का न केवल त्वरित संज्ञान लिया जा रहा है, बल्कि संबंधित विभागों की जवाबदेही भी स्पष्ट रूप से तय की जा रही है। एप पर प्राप्त शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे सड़कों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। इस एप की विशेषता है कि इसमें लोक निर्माण विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिला परिषद, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम सहित सभी संबंधित विभागों के अधीन आने वाली सड़कों का डेटा जियो-लोकेशन के साथ एकीकृत किया गया है। नागरिक किसी भी सड़क से संबंधित सड़क की जानकारी फोटो या वीडियो के माध्यम से सीधे एप पर अपलोड कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होते ही उसकी लोकेशन स्वतः संबंधित विभाग तक पहुंच जाती है और शिकायतकर्ता को एसएमएस के माध्यम से सूचना भी प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं म्हारी सड़क एप पर प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री की इस सीधी निगरानी से प्रशासनिक तंत्र में सक्रियता और जवाबदेही दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। म्हारी सड़क एप के माध्यम से शासन व्यवस्था और नागरिकों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम विकसित हुआ है, जिससे न केवल शिकायतों के समाधान में तेजी आई है, बल्कि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। यह पहल डिजिटल हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदेश की 63,170 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। म्हारी सड़क एप इस दिशा में एक सशक्त उपकरण के रूप में कार्य कर रही है, जो कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन दोनों को सुदृढ़ बना रही है। आम नागरिक अधिक से अधिक संख्या में इस एप का उपयोग करें और अपने क्षेत्र की सड़कों से संबंधित समस्याओं को साझा करें, ताकि सामूहिक प्रयासों से हरियाणा की सड़कों को सुरक्षित, सुगम और विश्वस्तरीय बनाया जा सके। म्हारी सड़क एप को कोई भी नागरिक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आसानी से उपयोग कर सकता है।

संक्षिप्त-समाचार

हरियाणा सिविल सचिवालय में महात्मा ज्योतिबा फुले एवं भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती का 24 अप्रैल को किया जाएगा संयुक्त आयोजन

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा समाज सुधार और सामाजिक न्याय के महान अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल 2026 को हरियाणा सिविल सचिवालय में संयुक्त रूप से समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा की जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सिविल सचिवालय की विभिन्न एसोसिएशनों के अनुरोध पर सरकार ने निर्णय लिया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती का संयुक्त समारोह 24 अप्रैल 2026 को प्रातः 11:00 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ के ग्राउंड फ्लोर स्थित एमआईपी (एमआईपी) प्रवेश द्वार के सामने आयोजित किया जाएगा। प्रवक्ता ने हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस गरिमामय आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य विभाग में 69 रिक्त पदों पर भर्ती किये जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट : आरती सिंह राव

चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही फिजियोथेरेपिस्ट के 69 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग में मांग पत्र भेजा गया है। पहले विभाग द्वारा 54 रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने बारे लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजा गया था, अब संशोधित करके फिजियोथेरेपिस्ट के 69 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे यह भी बताया कि जींद जिला के गांव उझाना तथा करनाल जिला के गांव संभली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, इनमें उझाना सीएचसी निर्माण के लिए 2195.46 लाख रुपए की तथा संभली सीएचसी के लिए मुख्यमंत्री ने 2322.37 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। आरती सिंह राव ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में उपस्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी या अन्य स्वास्थ्य संस्थान खोलने की आवश्यकता हो, उस गाँव में जल्द से जल्द नियमानुसार शुरू किया जाए ताकि ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्वक, सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हों।

नगर परिषद रेवाड़ी और नगर पालिका धारूहेड़ा के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी

रेवाड़ी। नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका धारूहेड़ा के आम चुनाव व पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित स्थानों और तय समय सीमा में करवाई जा रही है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा 10 मई को कराए जाने वाले चुनाव व उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 25 अप्रैल 2026 तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन कर सकते हैं। वीरवार, 23 अप्रैल तक नगर परिषद रेवाड़ी चेयरपर्सन पद के लिए 2 और नगर पालिका धारूहेड़ा चेयरपर्सन पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन जमा करवाया है। वहीं नगर परिषद रेवाड़ी में वार्डों के पार्षद पदों के लिए अलग-अलग वार्डों से 27 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसी प्रकार नगर पालिका धारूहेड़ा के वार्डों के पार्षद पदों के लिए विभिन्न वार्डों से 16 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज करवाए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत राज संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए वीरवार, 23 अप्रैल तक किसी ने भी नामांकन दर्ज नहीं करवाया है। नगर परिषद रेवाड़ी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त राहुल मोदी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर परिषद रेवाड़ी में चेयरपर्सन पद के लिए उम्मीदवार लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर 202 में अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते है। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 से 11 के पार्षद पद के लिए नया मॉडल टाउन स्थित सेक्टर-1, ईओ एचएसवीपी कार्यालय में नामांकन दर्ज करवा सकते है।

निरोगी हरियाणा के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच की 5.86 करोड़ मुफ्त टेस्ट किए, कार्यक्रम का विस्तार अब बुजुर्गों तक

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- पूरे राज्य में पहुँच, बीमारी का जल्दी पता लगाना और 70 आयु वर्ग के नागरिकों तक विस्तार, निवारक स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा कदमः डॉ. सुमिता मिश्रा

हरियाणा सरकार के प्रमुख निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रम ह्यनिरोगी हरियाणाह्ल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच (स्क्रीनिंग) की जा चुकी है, जबकि 5.86 करोड़ से अधिक लैब टेस्ट निःशुल्क किए गए हैं। इससे राज्य में बीमारियों की समय पर पहचान और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक मजबूती मिली है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने यह बात उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल, 2026 तक इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों के 1,00,07,430 लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई इस पहल के तहत 5,86,60,875 मुफ्त लैब टेस्ट किए गए हैं, जिससे हजारों परिवारों का होने वाला खर्च कम हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में यह योजना उन परिवारों के लिए लागू की गई थी, जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये तक थी। अब इसका विस्तार कर 3 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों को भी शामिल किया गया है। इस बदलाव से लाभार्थियों की संख्या 1.59 करोड़ से बढ़कर लगभग 2.30 करोड़ हो गई है। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निदेर्शानुसार 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को, उनकी आय चाहे कितनी भी हो, इस योजना में शामिल किया जा रहा है। यह कदम बुजुर्गों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

डॉ मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम अब केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के घर-घर तक पहुंच बना रहा है। इसके तहत 1,11,116 आउटरीच कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 38.63 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स द्वारा 12,579 कैंप लगाकर लगभग 2.8 लाख लोगों तक सेवाएं पहुंचाई गईं। साथ ही, 25,907 आंगनवाड़ियों, 14,316 स्कूलों तथा 13,034 औद्योगिक एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग की गई है।

बार-बार लग रहे बिजली कटों से जनता बेहाल: सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा में गर्मी की शुरूआत होते ही बिजली संकट ने गंभीर रूप ले लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लंबे-लंबे बिजली कट लगाए जा रहे हैं। कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी अन्य कारणों का हवाला देकर दिनभर बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, जिससे आमजन, किसान, व्यापारी और विद्यार्थी सभी प्रभावित हो रहे हैं। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सैलजा ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर सोलर और बिजली बिल शून्य जैसे नारों से जनता को भ्रमित किया है। जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, जहां लोगों को भारी बिजली कटौती और बढ़े हुए बिलों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने लाखों रुपये खर्च कर अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगाए हैं, उन पर भी फिक्स चार्ज के नाम पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। यह नीति पूरी तरह विरोधाभासी और जनविरोधी है। कुमारी सैलजा ने कहा कि बिजली बिलों में पहले ही भारी बढ़ोतरी की जा चुकी है और अब अनियमित बिजली आपूर्ति ने जनता की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। छोटे व्यापारी, किसान और आम उपभोक्ता इस दोहरी मार से जूझ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि बिजली व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए, अनावश्यक कटौती पर रोक लगाई जाए और सोलर उपभोक्ताओं पर लगाए जा रहे फिक्स चार्ज को समाप्त किया जाए ताकि लोगों को वास्तविक राहत मिल सके।

सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं यह साबित करती हैं कि कानून का डर समाप्त होता जा रहा है। सरकार का ध्यान जनसुरक्षा की बजाय केवल प्रचार तक सीमित रह गया है। उन्होंने कहा कि जब शासन की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा न होकर केवल दावों और घोषणाओं तक सीमित रह जाए, तो ऐसी स्थिति में अपराध का बढना स्वाभाविक हो जाता है। सरकार को चाहिए कि कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करे और आम जनता में विश्वास बहाल करे।

प्रदूषण को लेकर हम आज सचेत न हुए तो आने वाली पीढ़ियों का दम घुट जाएगा : अनिल विज

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि ₹प्रदूषण को लेकर हम आज ही सचेत न हुए और इसके बारे में काम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों का दम घुट जाएगा क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए आक्सीजन नहीं मिल पाएगी₹ । श्री विज ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज के इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने का विशेष अभियान सराहनीय है। श्री विज से आज अभियान के संयोजक ब्रह्माकुमारी भारतभूषण सहित अन्य सदस्यों ने मुलाकात की और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदूषण को घटाने के लिए काफी प्रयास व काम करने की जरूरत है। लोगों को धरती पर अधिक से अधिक पेड़ व पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि उनसे ऑक्सीजन मिलती रहे और सरकारें भी प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कदम उठा रही है। प्रदूषण वाले चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और तकनीक में भी सुधार आ रहा है। लोक हित के विषय पर अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह अभियान पानीपत से श्रीनगर तक चलाया जा रहा है जोकि अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और देश में यात्रा निकाली जा रही है। एक यात्रा पानीपत से कश्मीर तक जा रही है। जैसा बताया गया यात्रा के दौरान जगह-जगह पर लोगों को विचारों से अवगत कराया जाएगा जोकि समय की आवश्यकता है।

हरियाणा में एचपीवी टीकाकरण अभियान तेज, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां राज्य स्तरीय संचालन समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए टीकाकरण अभियान के विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 14-15 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 2.26 लाख किशोरियों को कवर करने के लिए 2.28 लाख वैक्सीन डोज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि गत 22 अप्रैल तक राज्य में 13,500 से अधिक किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से 561 को अभियान के पहले दिन ही टीका लगाया गया।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा की सिंगल-डोज टीकाकरण रणनीति भविष्य में इस बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया, रेडियो, प्रिंट मीडिया और सामुदायिक मंचों के माध्यम से जागरूकता अभियान बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि वैक्सीन के बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांतियों को दूर कर लोगों का विश्वास बढ़ाया जा सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे वरिष्ठ डॉक्टरों, समुदाय के मौजिज लोगों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को चाहिए कि वह स्कूल प्राचार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर अभिभावकों को प्रेरित करे और टीकाकरण के लिए छात्राओं को निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी करे।

गौरतलब है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) एक सामान्य संक्रमण है, जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर (बच्चेदानी के निचले हिस्से का कैंसर) के लगभग 99.7 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है। एचपीवी वैक्सीन इस संक्रमण से बचाव करती है और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम करती है। भारत में महिलाओं में यह दूसरा सबसे आम कैंसर है और टीकाकरण इसके खिलाफ एक प्रभावी रोकथाम उपाय माना जाता है। यह वैक्सीन सुरक्षित व प्रभावी है और केन्द्र सरकार द्वारा वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद अनुमोदित की गई है। विश्व के 160 से अधिक देशों में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों के तहत यह वैक्सीन लगाई जा रही है।

प्रदेश में टीकाकरण प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा चिकित्सकीय निगरानी में किया जा रहा है। वैक्सीन के दुष्प्रभाव सामान्यतः बहुत मामूली होते हैं, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, बुखार या शरीर में दर्द। इन प्रभावों को डॉक्टर की सलाह अनुसार पैरासिटामोल से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। टीकाकरण के बाद किशोरियों का ध्यान रखने के लिए राज्य स्तरीय एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन (एईएफआई) कमेटी को सक्रिय किया गया है, जो किसी भी प्रतिकूल घटना की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी।

बैठक में बताया गया कि यह टीकाकरण अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। लाभार्थियों का पंजीकरण यू-विन प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, जो स्वतः टीकाकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों, वैक्सीनेटरों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अन्त्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, श्रम तथा युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री रिपुदमन सिंह ढिल्लों, सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खांगवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजदू रहे। जिलों से उपायुक्त, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) और फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई) के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

संपादकीय

'नरक का कुआँ' से 'महान देश' तक – ट्रम्प की दोहरी भाषा का सच

अमेरिकी राजनीति में एक पुरानी कहावत चरितार्थ होती दिखती है - 'जो आज मित्र है, वह कल शत्रु हो सकता है, और जो कल शत्रु था, वह परसों फिर मित्र बन सकता है।' डोनाल्ड ट्रम्प स्वयं इस कहावत को जीवंत करने में कभी पीछे नहीं रहे। एक ओर वे भारत को 'महान देश' और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'शीर्ष पर बैठा बहुत अच्छा मित्र' बताते हैं, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक ऐसी सामग्री साझा करते हैं जिसमें भारत को 'नरक के गड्ढे' जैसे देशों की श्रेणी में रखा गया है। यह विरोधाभास केवल एक व्यक्ति की सनक नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति की उस जटिल मानसिकता का दर्पण है जो एक साथ दो नावों पर सवार रहती है। मामला यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर एक अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार माइकल सैविज की एक लंबी टिप्पणी को पुनः साझा किया। यह टिप्पणी अमेरिका में 'जन्मसिद्ध नागरिकता' यानी बर्थराइट सिटीजनशिप के मुद्दे पर थी। सैविज ने इस बहस के दौरान भारत और चीन को उन देशों में शामिल किया जहाँ से लोग अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर नागरिकता हासिल करते हैं। उनके शब्द न केवल अशोभनीय थे, बल्कि दो प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर तीखी चोट करने वाले थे। ट्रम्प ने इस सामग्री को बिना किसी टिप्पणी या आपत्ति के साझा किया, जिसका अर्थ यह निकाला गया कि वे इससे सहमत हैं या कम से कम इसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। जन्मसिद्ध नागरिकता का यह विवाद नया नहीं है। ट्रम्प जनवरी २०२५ में सत्ता में लौटने के बाद से ही इसे समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक कार्यकारी आदेश भी जारी किया जिसके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में अमेरिकी धरती पर जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का बड़ा वर्ग मानता है कि अमेरिकी संविधान का चौदहवाँ संशोधन इस अधिकार की गारंटी देता है और इसे किसी कार्यकारी आदेश से नहीं बदला जा सकता। यह मामला अब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ट्रम्प स्वयं इस मुकदमे की सुनवाई में उपस्थित हुए - एक बैठे हुए राष्ट्रपति के लिए यह एक ऐतिहासिक, यद्यपि विवादास्पद, कदम था। लेकिन असली सवाल यह है कि ट्रम्प ने ऐसी सामग्री को क्यों साझा किया जो भारत जैसे रणनीतिक साझेदार की गरिमा को ठेस पहुँचाती है? इसके दो संभावित उत्तर हैं। पहला - यह उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। अपने समर्थक वर्ग को सक्रिय रखने के लिए वे अप्रवासन विरोधी भावनाओं को हवा देते रहते हैं, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दूसरा - यह उनकी सुविचारित नीति नहीं, बल्कि आवेग में लिया गया निर्णय है जो उन्हें कभी-कभी महंगा पड़ता है। दोनों ही स्थितियाँ भारत के लिए चिंताजनक हैं। भारत-अमेरिका संबंध आज कई स्तंभों पर टिके हैं - व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक समन्वय। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। तकनीकी क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं ने अमेरिका को जो योगदान दिया है, वह किसी से छिपा नहीं। सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक, भारतीय मूल के पेशेवरों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयाँ दी हैं। ऐसे में जब एक टिप्पणीकार इन्हें 'लैपटॉप लेकर घूमने वाले गुंडे' कहे और राष्ट्रपति उसे अपने मंच से प्रसारित करें, तो यह केवल शाब्दिक अपमान नहीं रहता - यह एक संकेत बन जाता है। भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई कड़ी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से नहीं आई है, जो भारतीय कूटनीति की परंपरागत शैली के अनुकूल है - धीरज रखो, पर्दे के पीछे बात करो, और संबंधों की व्यापक तस्वीर को सामने रखो। यह परिपक्व रणनीति है, परंतु इसकी एक सीमा भी है। यदि ऐसे अपमानजनक बयान बार-बार आते रहें और भारत की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आए, तो यह संदेश जाता है कि भारत को अनदेखा किया जा सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है जो जन्मसिद्ध नागरिकता देता है - यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। लगभग तीन दर्जन देश, जिनमें कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं, यही व्यवस्था अपनाते हैं। लेकिन ट्रम्प के बयान की सबसे बड़ी ताकत उनकी सच्चाई नहीं, उनकी दोहराव और आत्मविश्वास है। वे जो कहते हैं, उसे इतनी दृढ़ता से कहते हैं कि उनके समर्थक उसे सत्य मान लेते हैं। भारत को इस पूरे प्रकरण से एक व्यावहारिक सबक लेना चाहिए। मैत्री के आश्वासन और वास्तविक नीतिगत सम्मान दो अलग-अलग चीजें हैं। 'शीर्ष पर बहुत अच्छा मित्र' जैसे जुमले कूटनीतिक बैठकों की शोभा बढ़ा सकते हैं, परंतु जब वही नेता ऐसी सामग्री को प्रसारित करे जो आपके देश और आपके नागरिकों को अपमानित करे, तो मित्रता की परिभाषा पर पुनर्विचार आवश्यक हो जाता है। भारत एक उभरती हुई विश्वशक्ति है। उसकी आर्थिक वृद्धि, जनसांख्यिकीय शक्ति और भू-राजनीतिक स्थिति उसे किसी भी देश के लिए अनिवार्य साझेदार बनाती है। ऐसे में भारत को न केवल अपने हितों की रक्षा करनी है, बल्कि अपनी गरिमा की भी। कूटनीति विनम्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के बीच संतुलन साधना ही सच्ची कूटनीतिक दक्षता है। अंत में, ट्रम्प की राजनीति को समझने की एक सरल कुंजी है - वे वही करते हैं जो उन्हें राजनीतिक लाभ दे। आज यदि भारत उनके लिए उपयोगी है, तो वे 'महान देश' कहेंगे। कल यदि घरेलू राजनीति की जरूरत पड़ी, तो वे बिना झिझक वही सामग्री साझा करेंगे जो आपको 'नरक का कुआँ' बताए। भारत को इस समीकरण को समझते हुए अपनी विदेश नीति को अमेरिका-केंद्रित नहीं, बल्कि भारत-केंद्रित बनाना होगा - जहाँ संबंध महत्त्वपूर्ण हों, परंतु आत्म-सम्मान सर्वोपरि।

यंत्र की चमक बताएगी शरीर में निकोटिन की मात्रा

राजेश चंद्र बाली

भारत सरकार के नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (इंस्ट), मोहाली ने एक नई सामग्री विकसित की है जो फ्लोरोमेट्रिक सेंसिंग के माध्यम से मानव शरीर में निकोटिन और कोटिनिन की मात्रा का पता लगा सकती है। फ्लोरोमेट्रिक सेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जो फ्लोरोसेंट उत्सर्जन का उपयोग करके विभिन्न मापदंडों को मापती है।

वर्तमान मामले में, यह सामग्री, जो एक सेंसर के रूप में कार्य करती है, निकोटीन या कोटीनिन के संपर्क में आने पर तेजी से चमकने लगती है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में तंबाकू के संपर्क का शीघ्र पता लगाने और समय पर कार्रवाई करने में यह उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आमतौर पर इस सामग्री की चमक बहुत कम होती है, लेकिन जब यह सेंसर इन हानिकारक रसायनों के संपर्क में आता है, तो इसकी चमक अत्यधिक तीव्र हो जाती है। इससे अनुसंधान मौजूदा तरीकों की तुलना में काफी आसान और त्वरित हो जाता है। नई तकनीक से, छोटी से छोटी मात्रा की भी तेजी और सटीकता से पहचान की जा सकती है, जो स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

यह सामग्री एक लौह-आधारित धातु-जैविक फ्रेमवर्क (एफई-एमओएफ) है, जिसका सामान्य अर्थ है कि यह लोहे और जैविक अणुओं से बनी एक बहुत ही सूक्ष्म संरचना है। यह संरचना मानव बाल से हजारों गुना छोटी होती है और इसमें बहुत छोटे छिद्र होते हैं जो अन्य अणुओं को फंसाने और उनके साथ क्रिया करने की क्षमता रखते हैं।

आईएनएसटी (इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी) की वैज्ञानिक मोनिका सिंह ने अपनी शोध छात्रा अर्शमिंदर कौर के साथ मिलकर इस तकनीक को विकसित किया है। उन्होंने कहा कि यह अभी इन विट्रो चरण में है, लेकिन जैविक प्रणालियों में उपयोग के लिए सुरक्षित पाया गया है। प्रयोगों में यह साबित हुआ कि यह जैव-अनुकूल है, जिसका अर्थ है कि यह जीवित कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे कोशिका स्तर पर वास्तविक समय की निगरानी संभव हो पाती है। उन्होंने कहा कि लंबे समय में, इस तकनीक का उपयोग रक्त के नमूनों के माध्यम से शरीर में निकोटीन और कोटिनिन की प्रतिशत मात्रा का पता लगाने के लिए भी किया जा सकेगा। इस मैटीरियल का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह पानी में और विभिन्न परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कार्य करता है। यह शरीर में मौजूद अन्य सामान्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है, जिससे यह सटीक परिणाम देता है। अनेक बार उपयोग करने के बाद भी यह मैटीरियल प्रभावी तरीके से काम करता रहता है, जिससे यह पुनः प्रयोज्य और लागत-प्रभावी बन जाता है।

यह शोध विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इस तरह की सामग्री का उपयोग कोटिनिन की व्यापक फ्लोरोसेंस के माध्यम से पहचान के लिए किया गया है। यह साधारण परीक्षण किटों के विकास के लिए नई संभावनाएँ खोलता है, जो धूम्रपान करने वालों के लिए और दूसरे हाथ के धुएँ के संपर्क की निगरानी के लिए लाभदायक हो सकती हैं।

वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में यह तकनीक डॉक्टरों, शोधकताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों को तंबाकू के संपर्क का तेजी से पता लगाने तथा समय पर कार्रवाई करने में मदद करेगी। यह जन स्वास्थ्य अभियानों को भी समर्थन दे सकती है क्योंकि यह आसान और किफायती परीक्षण विधियाँ प्रदान कर सकती है। कुल मिलाकर, यह नवीनतम सामग्री बेहतर स्वास्थ्य निगरानी और धूम्रपान-मुक्त समाज की ओर एक आशाजनक कदम है, क्योंकि हर साल दुनिया भर में लाखों लोग तंबाकू जनित बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं।

(लेखक भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में आकाशवाणी, जालंधर में सहायक निदेशक, समाचार-सह-क्षेत्रीय समाचार प्रमुख के रूप में तैनात हैं।)

पंचायत से संसद तकः नारी नेतृत्व, डिजिटल सुशासन और विकसित भारत का संकल्प

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

जब कोई राष्ट्र अपनी जड़ों को सींचता है, तो उसकी शाखाएं आसमान छूती हैं। भारत की वे जड़ें उसकी पंचायतें हैं और उन पंचायतों की आत्मा आज उसकी महिलाएं हैं। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जब गांवों की सरकार को संवैधानिक मान्यता मिली, तो भारतीय लोकतंत्र ने एक नया अध्याय लिखा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पंचायती राज को नई ऊर्जा और दिशा मिली है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सत्ता केवल दिल्ली के गलियारों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के अंतिम गांव की दहलीज तक पहुंचे। 'विकसित भारत 2047' का विजन 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की मजबूत नींव पर आधारित है, जो देश की लगभग 64 प्रतिशत जनसंख्या की जीवनरेखा हैं।

लोकतंत्र की पाठशालाः नारी नेतृत्व का उदय

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 एक विशेष गौरव के साथ मनाया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज संस्थाओं को देश में महिला नेतृत्व की सबसे बड़ी पाठशाला बताया

यह उस वास्तविकता की स्वीकृति थी जो आज ग्रामीण भारत में प्रतिदिन घटित हो रही है।

देशभर में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या 32 लाख से अधिक है। वर्तमान में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, 24,41,781 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 12,14,885 महिलाएँ हैं, जो कुल का लगभग 49.75 प्रतिशत हैं। 21 राज्यों तथा 2 केन्द्र शासित प्रदेशों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण लागू किया है। पिछले चार वर्षों में संचयी रूप से 33.50 लाख महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व एवं सुशासन पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है - और 2025-26 में ही 9.37 लाख महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 47.7 प्रतिशत की वृद्धि है।

सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और नारी शक्ति वंदन अधिनियम

'सशक्त पंचायत नेत्री अभियान' महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों, अधिकारों और नेतृत्व क्षमताओं के प्रति सजग और सक्षम बनाता है। 'महिला-हितैषी ग्राम पंचायत' और 'निर्भय रहो' जैसी पहलें महिलाओं को जमीनी लोकतंत्र में सुरक्षित और सशक्त भागीदारी के लिए प्रेरित कर रही हैं। 'निर्भय रहो' निर्भया फंड के अंतर्गत संचालित है और यह कानूनी जागरूकता, सामाजिक संवेदनशीलता एवं तकनीकी सशक्तिकरण को एकीकृत करते हुए ग्रामीण शासन में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम - लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करते हुए - भारतीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका को स्थायी और सशक्त रूप से स्थापित करता है। पंचायतों की पाठशाला में तैयार महिला नेतृत्व ही विधानसभाओं और संसद में बदलाव की वाहक बनेगी।

सोलहवाँ वित्त आयोगः संसाधनों में अभूतपूर्व वृद्धि

वित्तीय सशक्तिकरण किसी भी संस्था की कार्यक्षमता की आत्मा होती है। 16वें वित्त आयोग ने 2026 से 2031 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को 4.35 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आवंटन किया है - जो 15वें वित्त आयोग की तुलना में 84 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 में ही 1.40 लाख करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित है। यह वित्तीय सुदृढ़ता पंचायतों को केवल खर्च करने की क्षमता नहीं देती, बल्कि उन्हें विकास के एजेंडा को स्वयं निर्धारित करने का आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। स्व-स्रोत राजस्व नीति और प्रदर्शन-आधारित अनुदान ने पंचायतों में जवाबदेही और प्रतिस्पर्धा - दोनों को एक साथ प्रोत्साहित किया है।

समावेशी और पारदर्शी शासन

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मार्गदर्शक मंत्र पंचायती राज मंत्रालय के प्रत्येक कदम का आधार है। ई-ग्राम स्वराज मंच के माध्यम से देशभर की ग्राम पंचायतों ने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऑनलाइन भुगतान संसाधित किए हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से एकीकृत यह मंच प्रत्येक लेनदेन को सीधे विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं तक वास्तविक समय में पहुंचाता है। 2.5 लाख से अधिक पंचायतों और 1.6 करोड़ वेंडर्स का इससे जुड़ना डिजिटल सुशासन की व्यापक स्वीकृति का प्रमाण है। वर्ष 2025-26 में 2.5 लाख से अधिक पंचायतों ने सतत विकास लक्ष्यों को 9 थीम्स में विभाजित कर अपनी विकास योजनाएँ स्वयं तैयार कीं - ग्रामीण विकास को लक्ष्य-उन्मुख और परिणाम-केंद्रित बनाते हुए।

पेसा रैंकिंगः अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की नई पहल

पंचायती राज मंत्रालय ने पहली बार 25 जनवरी 2026 को वर्ष 2024-25 के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के अंतर्गत राज्यों के प्रदर्शन की राज्यवार रैंकिंग जारी की। इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करना तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा आधारित स्वशासन को मजबूत करना है।

इस रैंकिंग में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश फ्रंट रनर श्रेणी में रहे; राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना परफॉर्मर श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और गुजरात आकांक्षी श्रेणी में शामिल हैं। यह रैंकिंग दस पेसा राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना - की प्रगति, क्षमता और संभावनाओं को रेखांकित करती है। सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप, मंत्रालय पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों के साथ निरंतर समन्वय और सहयोग कर रहा है।

सभासार और एआई-सक्षम शासनः जनभाषा में जनतंत्र की आवाज

पंचायती राज मंत्रालय ने कृत्रिम मेधा को शासन के केंद्र में लाकर एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। 14 अगस्त 2025 को लॉन्च 'सभासार' अब 23 भारतीय भाषाओं में ग्राम सभा की कार्यवाही दर्ज करता है। 1,11,486 ग्राम पंचायतें इसका उपयोग कर चुकी हैं - भाषा अब भागीदारी के मार्ग में बाधा नहीं।

स्वामित्व योजनाः संपत्ति अधिकारों से आर्थिक सशक्तिकरण

स्वामित्व योजना ने ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से 3.30 लाख गांवों में सर्वे पूरा कर 3.13 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए हैं। यह ग्रामीण परिवारों को बैंक ऋण और औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ रहा है, संपत्ति को आर्थिक संपदा में बदलने का अवसर दे रहा है, भूमि एवं संपत्ति से जुड़े विवादों को कम कर रहा है, और ग्राम पंचायतों के लिए एक स्थायी तथा पारदर्शी राजस्व स्रोत के रूप में उभर रहा है।

संस्थागत क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 2022-23 से अब तक संचयी रूप से 1.62 करोड़ से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है - केवल 2025-26 में 45.24 लाख लोग प्रशिक्षित हुए। आईआईएम और आईआईटी के साथ साझेदारी में नेतृत्व विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार' अभियान के तहत 2.15 लाख पंचायतों ने 954 सेवाओं का सिटिजन चार्टर तैयार किया है।

विकसित भारत 2047ः गांव से उठेगी नई सुबह

'विकसित भारत 2047' का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं - यह सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन और समावेशी प्रगति का व्यापक दृष्टिकोण है। 21 राज्यों में 50 प्रतिशत महिला भागीदारी, 3 लाख करोड़ का डिजिटल लेनदेन, 23 भाषाओं में ग्राम सभा की आवाज, 16वें वित्त आयोग का ऐतिहासिक आवंटन और सशक्त पंचायत नेत्री अभियान - ये सब मिलकर विकसित भारत की नींव की ईंटें हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस अवसर पर देश की उन 14 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधियों को सादर नमन, जो प्रतिदिन अपने गांव और देश को बेहतर बनाने में जुटी हैं। यही नारी शक्ति है, यही नव भारत की तैयारी है।

लेखक केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री हैं।

आज का राशिफल

मेषः आज का दिन सुख-सुविधाओं का आनंद दिलाने वाला रहेगा। हालांकि कार्यस्थल पर सहकर्मियों का अनावश्यक हस्तक्षेप आपकी एकाग्रता भंग कर सकता है। घर में धार्मिक या आध्यात्मिक माहौल बन सकता है। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः करियर के लिहाज से दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। विदेशी कंपनियों से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ गंभीर विषयों पर चर्चा आपके दृष्टिकोण को मजबूत करेगी। टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक लाभ होने के योग हैं। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के बीच मतभेद उभर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। आप पर काम का दबाव भी रहेगा, लेकिन अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे। छोटी-सी गलती बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बढ़ेगा। कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने मित्रों और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। जिम्मेदारियों को सहजता से निभा पाएंगे। कार्य के प्रति समर्पण आपको सफलता दिलाएगा और आप अपनी प्रतिभा का बेहतरीन उपयोग करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः जल्दबाजी में लाभ पाने की सोच नुकसान दे सकती है। कानूनी मामलों में उलझने से बचें। शुभ कार्यों में खर्च बढ़ सकता है। कुछ लोग स्वार्थवश आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। छात्रों को अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और परिणाम मिलने में समय लग सकता है। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः व्यापार में नए अनुबंध लाभदायक साबित होंगे। परिवार के लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। मीडिया, लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार है। आप अपनी कमियों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः कामकाज में उत्कृष्ट परिणाम मिलने के संकेत हैं। आय और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा। रिसर्च या अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ सकती है। आत्ममंथन के लिए यह दिन उपयुक्त है। परिवार में विचारों का अच्छा तालमेल रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः नए व्यापार की शुरूआत के लिए समय अनुकूल है। बिना मांगे सलाह देने से बचें और किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। अधिकारी वर्ग के साथ बातचीत में संयम रखें, क्योंकि उनकी बातें आपको आहत कर सकती हैं। *(सिटी दर्पण)*

धनुः आज काम में मन कम लगेगा और दांपत्य जीवन में अहंकार के कारण टकराव हो सकता है। मानसिक तनाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। बड़े फैसले सोच-समझकर लें। प्रेम संबंधों में भी कुछ असंतुलन रह सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर विवाद उभर सकता है। *(सिटी दर्पण)*

मकरः आप अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से डटे रहेंगे। बीमार लोगों की सेहत में सुधार होगा। सरकारी कामों में अटकी फाइल आगे बढ़ सकती है। पारिवारिक मामलों को शांतिपूर्वक सुलझाने में सफलता मिलेगी। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः गलत या अनैतिक कार्यों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। मानसिक तनाव के कारण शरीर में थकावट महसूस हो सकती है। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है। *(सिटी दर्पण)*

मीनः दांपत्य जीवन में आपसी सम्मान बनाए रखने की जरूरत है। अपनी बातों को जीवनसाथी पर थोपने से बचें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। छात्र अपने करियर को लेकर गंभीर रहेंगे। शेयर बाजार से लाभ मिल सकता है। *(सिटी दर्पण)*

बीमा से क्यों दूर है आम भारतीय

डॉ. सत्यवान सौरभ (ह.स)

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। ऊंची विकास दर, डिजिटल क्रांति, बढ़ती आय और वैश्विक मंच पर मजबूत होती स्थिति- ये सब संकेत देते हैं कि देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक सच्चाई ऐसी भी है, जो अक्सर नजरों से ओझल रह जाती है- भारत का आम नागरिक अब भी आर्थिक सुरक्षा के सबसे बुनियादी साधन यानी बीमा से दूर है। विडंबना यह है कि जिस देश में अनिश्चितताओं की भरमार है- बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं, रोजगार की अस्थिरता- वहीं बीमा को अब भी अतिरिक्त खर्च समझा जाता है, न कि जरूरी सुरक्षा कवच।

भारत में बीमा कवरेज की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बीमा घनत्व और पैठ दोनों वैश्विक औसत से नीचे हैं। ग्रामीण भारत, जो देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, वहां बीमा की पहुंच बेहद सीमित है। जीवन बीमा के कुछ प्रसार के बावजूद स्वास्थ्य, फसल और संपत्ति बीमा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि विकास की रफ्तार के साथ बीमा का दायरा नहीं बढ़ पा रहा?

इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है- जागरूकता की कमी। देश के बड़े हिस्से को आज भी यह समझ नहीं है कि बीमा आखिर है क्या और यह उनके जीवन में किस तरह सुरक्षा प्रदान कर सकता है। गांवों में तो बीमा को अक्सर ठगी या धोखे के रूप में देखा जाता है। एजेंटों द्वारा गलत जानकारी देना, पॉलिसी की शर्तों को स्पष्ट न करना और क्लेम के समय होने वाली परेशानियां लोगों के मन में अविश्वास पैदा करती हैं। परिणामस्वरूप, लोग बीमा से दूरी बनाए रखना बेहतर समझते हैं।

दूसरा बड़ा कारण है, आर्थिक प्राथमिकताएं। जब किसी परिवार की आय सीमित हो और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना ही चुनौती हो, तब बीमा जैसी चीज उनके लिए प्राथमिकता में नहीं आती। आम भारतीय के लिए पहले भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की जरूरतें हैं; बीमा उसके बाद आता है। यह सोच गलत नहीं है लेकिन यह भी सच है कि एक छोटी-सी दुर्घटना या बीमारी पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को हिला सकती है और यही वह जगह है जहां बीमा की जरूरत सबसे ज्यादा होती है।

तीसरा कारण है, बीमा उत्पादों की जटिलता। बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पाद आम लोगों की समझ से परे होते हैं। लंबी-चौड़ी शर्तें, तकनीकी भाषा और अस्पष्ट लाभ- ये सब मिलकर बीमा को एक कठिन और उलझा हुआ उत्पाद बना देते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि कौन-सी पॉलिसी उसके लिए सही है। इस जटिलता का फायदा कई बार एजेंट उठाते हैं और ग्राहक को ऐसी पॉलिसी बेच दी जाती है, जो उसकी जरूरतों के अनुकूल नहीं होती।

इसके साथ ही, दावा निपटान की प्रक्रिया भी बीमा से आमजनों की दूरी का एक बड़ा कारण है। अक्सर सुनने को मिलता है कि क्लेम के समय कंपनियां तकनीकी कारणों का हवाला देकर दावे खारिज कर देती हैं या प्रक्रिया को इतना लंबा कर देती हैं कि ग्राहक थक हार कर पीछे हट जाता है। इस तरह के अनुभव समाज में तेजी से फैलते हैं और लोगों के मन में धारणा बन जाती है कि बीमा केवल पैसे वसूलने का माध्यम है, न कि संकट के समय सहायता का।

वितरण प्रणाली की कमजोरी भी अहम कारण है। बीमा अब भी बड़े पैमाने पर एजेंट आधारित मॉडल पर निर्भर है, जिसकी पहुंच सीमित है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में एजेंटों की कमी है और जहां हैं भी, वहां उनकी प्राथमिकता कमीशन कमाना होता है, न कि ग्राहक को सही सलाह देना। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण इसका लाभ हर वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहा।

इन सबके बीच सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारतीय समाज में अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं को 'भगवान की मर्जी' मान लिया जाता है। जोखिम प्रबंधन की सोच अभी भी व्यापक नहीं हो पाई है। लोग यह मानते हैं कि बुरा वक्त आएगा तो किसी न किसी तरह संभाल लिया जाएगा- पर यह सोच कई बार भारी पड़ जाती है।

हालांकि, हाल के वर्षों में सरकार ने बीमा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीब और निम्न आय वर्ग को बीमा के दायरे में लाने की कोशिश की है। इन योजनाओं ने यह साबित किया है कि यदि बीमा सस्ता, सरल और सुलभ हो तो लोग इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन योजनाओं का दायरा अभी भी सीमित है और व्यापक स्तर पर बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

हाल ही में पारित 'बीमा कानून संशोधन विधेयक, 2025' इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से प्रबंध महाधिवक्ता (एमजीए) की अवधारणा बीमा क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल सकती है। एमजीए स्थानीय स्तर पर काम करते हुए बीमा उत्पादों को अधिक प्रासंगिक और सुलभ बना सकते हैं। इससे वितरण प्रणाली मजबूत होगी, उत्पादों में नवाचार आएगा और दावा निपटान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सकती है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया गया तो यह बीमा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

केवल नीतिगत सुधार पर्याप्त नहीं हैं। असली चुनौती इन सुधारों को जमीन पर उतारने की है। इसके लिए सबसे पहले बीमा को उत्पाद नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में स्थापित करना होगा। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को मौलिक जरूरत माना जाता है, वैसे ही बीमा को भी सामाजिक सुरक्षा के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना होगा।

जागरूकता अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, मीडिया के माध्यम से सरल भाषा में बीमा की जानकारी देना और स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना जरूरी है। इसके साथ ही, बीमा उत्पादों को सरल और पारदर्शी बनाना होगा, ताकि आम व्यक्ति बिना किसी भ्रम के सही निर्णय ले सके।

नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि बीमा कंपनियां ग्राहकों के हितों को प्राथमिकता दें, दावा निपटान की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाएं और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई करें। डिजिटल तकनीक का उपयोग इस दिशा में सहायक हो सकता है, लेकिन इसके साथ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।

अंततः, यह समझना होगा कि बीमा केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र है। यह उस भरोसे का नाम है, जो व्यक्ति को अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। जब तक यह भरोसा मजबूत नहीं होगा, तब तक बीमा का दायरा सीमित ही रहेगा। भारत के लिए 'सबका बीमा, सबकी रक्षा' केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हर नागरिक को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना होगा। यह तभी संभव है, जब बीमा को आम भारतीय के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। वरना विकास की यह दौड़ अधूरी रह जाएगी, जहां चमक तो होगी लेकिन सुरक्षा का साया नहीं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

स्वास्थ्य विभाग आशा वर्करों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीवन बीमा समझौता सुनिश्चित करे: हरपाल सिंह चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब में जमीनी स्तर पर काम कर रहे जरूरी स्वास्थ्य कर्मियों की भलाई के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि वह आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों को दिए जाने वाले मानदेय (इंसेंटिव) में जरूरी बढ़ोतरी की वकालत करते हुए केंद्र सरकार को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखे।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार से मौजूदा योजना के तहत इन भुगतानों को बढ़ाने की अपील की जानी चाहिए, जो केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के वित्तीय अनुपात पर काम करती है।

आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स सांझा मोर्चा, पावरकॉम एंड ट्रांसको ठेका मुलाजिम यूनियन और पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकों की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) को भी निर्देश दिए कि पावरकॉम एंड ट्रांसको ठेका मुलाजिम यूनियन की मांगों के समाधान के लिए एक ठोस नीति बनाई जाए।

आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स सांझा मोर्चा की मांगों पर विस्तार से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इन वर्करों की तत्काल सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा, ह्लस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को हिदायत दी गई है कि वह सभी आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों के लिए जीवन बीमा कवरेज सुनिश्चित करने हेतु किसी बैंकिंग संस्था के साथ समझौता करे।ह्व

उन्होंने आगे कहा, यूनियन द्वारा उठाई गई जायज मांगें, जिन्हें सीधे विभागीय स्तर पर हल किया जा सकता है, उन्हें प्रशासनिक बैठकों और निर्णायक कार्रवाई के जरिए बिना किसी देरी के तुरंत हल किया जाना चाहिए।

राज्य के बिजली क्षेत्र के कर्मियों की चिंताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पावरकॉम एंड ट्रांसको ठेका मुलाजिम यूनियन के साथ विस्तृत बैठक की। उन्होंने उन्हें पेश आ रही कार्य संबंधी मुश्किलों और आउटसोर्सड रोजगार से सेवाएँ कांट्रैक्ट में बदलाव की उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया।

मांगों के संरचनात्मक समाधान पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर बसंत गर्ग को सीधे निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इन आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कॉरपोरेशन स्तर पर तुरंत ठोस नीति तैयार करें।

कर्मचारियों के साथ बैठकों की इस श्रृंखला के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें उनके मुद्दों पर भरोसा दिलाया। उन्होंने यूनियन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

सरकार के रुख को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के समर्पित नेतृत्व में आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता से विचार किया जा रहा है और निष्पक्ष समाधान के लिए सक्रिय समीक्षा की जा रही है।

इन बैठकों के दौरान आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स सांझा मोर्चा की ओर से अमरजीत कौर, राणो, हरिंदर कौर शतराना और संतोष कुमार, पावरकॉम एंड ट्रांसको ठेका मुलाजिम यूनियन की ओर से बलिहार सिंह, टेक चंद और शेर सिंह तथा पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स की ओर से गुरबाज सिंह, पवनबीर सिंह और गुरविंदर सिंह ने अपने मुद्दे और मांगें पेश कीं।

पंजाब सरकार द्वारा आश्रित बच्चों के लिए 35.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी; 2.36 लाख से अधिक बच्चों को लाभ : डॉ. बलजीत कौर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आश्रित और जरूरतमंद बच्चों के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान मार्च माह के लिए पंजाब सरकार ने 35.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है, जिससे राज्य भर के 2.36 लाख से अधिक जरूरतमंद बच्चों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है।

उन्होंने बताया कि इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 432.78 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक आश्रित बच्चों को निरंतर वित्तीय सहायता दी जा सके। इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस योजना से लाखों आश्रित बच्चों को लाभ मिल रहा है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण अपने भविष्य से वंचित न रह जाए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जन-हितैषी और मानवीय सोच वाली योजनाओं को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को शामिल किया जाता है जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके माता-पिता का निधन हो चुका हो, या वे लापता हों, अथवा माता-पिता शारीरिक या मानसिक रूप से परिवार की देखभाल करने में सक्षम न हों। इस योजना के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता से ऐसे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलती है। डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े हर बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य एक सुरक्षित, समावेशी और प्रगतिशील पंजाब का निर्माण करना है, जहां हर बच्चे को आगे बढ़ने और अपने भविष्य का निर्माण करने के समान अवसर मिल सकें।

सीमा पार से चल रहे नशे और हथियारों की तस्करी मॉड्यूल का पदार्फाश; 900 ग्राम आईसीई और 5 पिस्तौल समेत तीन आरोपी अमृतसर से गिरफ्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/अमृतसर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तीन आरोपियों को 915 ग्राम आईसीई (मेथामफेटामाइन) और पांच आधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर सीमा पार से नशे और हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का पदार्फाश किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ सुख्खा (21), सोला सिंह उर्फ सोनू (29) और करन सिंह (22) के रूप में हुई है, जो सभी फिरोजपुर के गांव साहांके के निवासी हैं। बरामद पिस्तौलों में दो 9 एमएम ग्लॉक और तीन .30 बोर पिस्तौल तथा दो जिंदा कारतूस शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी जा रही नशे और हथियारों की खेप प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोपी नशे और अवैध हथियारों की सप्लाई के लिए स्थानीय हैंडलर के रूप में काम कर रहे थे। डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क का पदार्फाश करने के लिए मामले में आगे-पीछे के सभी संबंधों की जांच जारी है।

कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए लक्षित ऑपरेशन में पुलिस टीमों ने संदिग्ध सुखविंदर सिंह उर्फ सुख्खा, सोला सिंह उर्फ सोनू और करन सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पहले केवल एक .30 बोर पिस्तौल बरामद हुआ था और आरोपियों से पूछताछ के दौरान हुए खुलासों के आधार पर उनके पास से 915 ग्राम आईसीई और चार अन्य पिस्तौल बरामद किए गए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि फिरोजपुर सेक्टर के घने जंगलों में नशे और हथियारों की खेप फेंकी जा रही थी। आरोपी ऐसे स्थानों से इन खेपों को प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में इसकी सप्लाई करते थे।

इस संबंध में थाना गेट हकीमा, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22-सी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (6, 7(८) और 8) के तहत एफआईआर नंबर 105 दिनांक 15-04-2026 को दर्ज की गई है।

श्रम कल्याण बोर्ड ने 7831 औद्योगिक श्रमिकों को 17.11 करोड़ के लाभ दिए : सौंद

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/एसएएस नगर

राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनकी भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत 7831 लाभार्थियों को 17.11 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

बोर्ड की चल रही गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंजाब के श्रम मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने इन प्रयासों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को जागरूकता अभियानों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक पात्र श्रमिक इन कल्याण योजनाओं का लाभ उठा सकें। मंत्री ने कहा कि जागरूकता की कमी अक्सर श्रमिकों को उनके लिए उपलब्ध कल्याण योजनाओं का लाभ लेने में बाधा बनती है।

योजनाओं के दायरे के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब श्रम कल्याण फंड अधिनियम, 1965 के तहत आने वाले संस्थानों में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में श्रमिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए चलायी गई हैं।

बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में चिकित्सा उपचार और सामान्य सर्जरी के लिए वित्तीय सहायता, एक्स-ग्रेशिया अनुदान, अंतिम संस्कार खर्च, एलटीसी, मातृत्व लाभ तथा मानसिक या शारीरिक दिव्यांगता वाले श्रमिकों के लिए सहायता शामिल है। इसके अलावा श्रमिक अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं, जिनमें शगुन योजना, चश्मा लगवाने संबंधी सहायता, दंत चिकित्सा देखभाल, श्रवण यंत्रों के लिए सहायता, तथा शिक्षा और दिव्यांगता मुआवजे हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल हैं।

मंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र श्रमिक तक कल्याण योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो और जरूरत के समय सुरक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने अधिकारियों से जागरूकता शिविर और सरल आवेदन प्रक्रियाओं सहित सक्रिय उपाय अपनाने की अपील की ताकि इन योजनाओं के दायरे और प्रभाव को और बढ़ाया जा सके।

पंजाब सरकार अपने विकास एजेंडे के एक अहम हिस्से के रूप में श्रम कल्याण को प्राथमिकता दे रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों को आवश्यक सहायता और उनका उचित सम्मान मिल सके।

इस अवसर पर श्रम विभाग के सचिव मनवेश सिंह सिद्धू, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव महिंदरपाल, श्रम आयुक्त-कम-कल्याण आयुक्त पंजाब राजीव कुमार गुप्ता, सदस्य बलदेव बलखंडी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पंजाब में बेअदबी विरोधी कानून लागू करने के लिए स्पीकर संधवां का विशेष सम्मान

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

गुरुद्वारा साहिब पातशाही दसवीं, कोटकपूरा में निहंग सिंहों के मुख्य सेवादार बाबा कुलवंत सिंह चाणकीया द्वारा पंजाब विधानसभा के स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान और स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां के ईमानदार और दृढ़ प्रयासों के कारण जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक 2026 लागू हुआ है, जिससे विश्व भर की संगत में खुशी की लहर है। कार्यक्रम के दौरान सुखमनी साहिब का पाठ, नितनेम बाणियां, अरदास और पावन हुक्मनामा के उपरांत बाबा कुलवंत सिंह चाणक्य ने कहा कि स्पीकर संधवां की विनम्रता और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने सभी को प्रभावित किया है। संधवां ने बाबा कुलवंत सिंह चाणकीया सहित समूची संगत का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह उपलब्धि संगत के सहयोग और गुरु जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाई है। पूर्व में विभिन्न पारंपरिक पार्टियों और संगठनों के नेता सत्ता में होने के बावजूद भी इस कार्य को लागू नहीं कर सके, जबकि अब कुछ लोग बेबुनियाद बयान देकर समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

पंजाब का नशों विरूद्ध युद्ध: मान सरकार के अधीन कार्रवाई तेज, एनडीपीएस मामलों में 40% वृद्धि, जब्तियों में बड़ा उछाल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- **2017-2021 के मुकाबले 2022-2026 के दौरान हेरोइन की बरामदगी में 148% वृद्धि; युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत तस्करी नेटवर्क पर कसा शिकंजा**
- **अभियान के सकारात्मक परिणाम आने लगे सामने; सजा दर 64% से बढ़कर 84%**
- **2017-2021 के मुकाबले नशा नेटवर्क के खिलाफ 2022 से अब तक बड़े स्तर पर कार्रवाई**

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाए जा रहे युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के प्रभावी, तेज और ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़े दर्शाते हैं कि नशों के खिलाफ कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, नशा तस्करी नेटवर्क को बड़े स्तर पर कमजोर किया गया है और दोषियों के खिलाफ सजा दर में भी महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2026 (अब तक) के दौरान 73,541 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2017-2021 के 52,255 मामलों की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाते हैं। गिरफ्तारियों की संख्या भी 68,064 से बढ़कर 98,596 हो गई है, जो राज्यभर में नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ लगातार और व्यापक कार्रवाई को दर्शाती है। जब्तियों के आंकड़े इस अभियान की सफलता को और स्पष्ट करते हैं। हेरोइन की बरामदगी में 148% का बड़ा उछाल दर्ज किया गया है– 2022 से अब तक 5,979 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, जबकि 2017-21 के दौरान यह मात्रा 2,412 किलोग्राम थी। अफीम की जब्ती में भी 43% से अधिक वृद्धि होकर यह 3,583 किलोग्राम तक पहुंच गई है, जो जमीनी स्तर पर तेज कार्रवाई को दशार्ती है। सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में विशेष रूप से उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। आइस (क्रिस्टल मेथामफेटामाइन) की जब्ती 17 किलोग्राम से बढ़कर 93 किलोग्राम हो गई है, जो 447% की वृद्धि है। कोकीन की जब्ती 6,064 किलोग्राम रही, जो पहले के 6,852 किलोग्राम के लगभग बराबर है। इस अभियान की पहुंच अब दवाइयों के दुरुपयोग तक भी बढ़ चुकी है। 2022-26 के दौरान 8.7 करोड़ गोलियां और कैप्सूल जब्त किए गए हैं, जो खासकर युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सप्लाई चेन पर बड़े प्रहार का संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम न्याय प्रणाली में भी दिखाई दे रहे हैं। दोषियों के लिए सजा दर बढ़कर 89% तक पहुंच गई है, जो मजबूत जांच, साक्ष्य संग्रह और प्रभावी अभियोजन को दशार्ती है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने कहा, यह केवल कार्रवाई में वृद्धि नहीं, बल्कि नशे के खतरे से निपटने के तरीके में एक मूलभूत बदलाव है। मामलों और जब्तियों में वृद्धि इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई को दशार्ती है, जबकि बढ़ती सजा दर यह दिखाती है कि मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा रहा है। सप्लायर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक पूरी श्रृंखला पर लगातार दबाव बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई की व्यापकता और निरंतरता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की स्पष्ट रणनीतिक सोच का परिणाम है, जिसके तहत युद्ध नशों विरुद्ध अभियान राज्यभर में सक्रिय और निर्णायक कार्रवाई का प्रमुख हिस्सा बन चुका है।

संक्षिप्त-समाचार

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को पूर्व सैनिकों से संबंधित सभी लंबित मामलों की व्यापक सूची तैयार करने के निर्देश दिए

चंडीगढ़। पंजाब के रक्षा सेवा कल्याण मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने आज रक्षा सेवा कल्याण विभाग के अधिकारियों को पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से संबंधित सभी लंबित मामलों की एक विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री भगत ने जोर देकर कहा कि लंबित मामलों के त्वरित, अधिक कुशल और पूरी पारदर्शिता के साथ निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मामले की स्थिति के बारे में सूची में स्पष्ट और सही ढंग से जानकारी दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और इस दिशा में सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि विभाग में खाली पदों पर भर्ती और बजट से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों के प्रति पूरा सम्मान रखती है।

फिनवेसिया ने इनोवेशन हैकाथॉन का किया आयोजन

चंडीगढ़। फिनवेसिया, एक वैश्विक मल्टी-डिसिप्लिनरी संगठन, जो डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है, ने चितकारा यूनिवर्सिटी और ईवाल्व एआई क्लब के सहयोग से अपने इनोवेशन हैकाथॉन का सफल आयोजन किया। इस पहल ने देश के प्रतिभाशाली युवा नवप्रवर्तकों को एक साथ लाकर आर्किटेक्चर-आधारित सोच और वास्तविक समस्याओं के समाधान के माध्यम से फिनटेक को नए सिरे से समझने का अवसर दिया। इस कार्यक्रम में फिनवेसिया के सह-संस्थापक एवं एमडी और जम्प के सीईओ सरवजीत सिंह विर्क, चीफ ग्रोथ ऑफिसर रमनिक घोटरा, ग्लोबल हेड एचआर एवं हेड स्ट्रेटेजी रीट वीरक, तथा चितकारा यूनिवर्सिटी के प्रो. (डॉ.) मीनू खुराना सहित कई शिक्षाविद उपस्थित रहे। यह हैकाथॉन पारंपरिक कोडिंग प्रतियोगिता से आगे बढ़कर एक रणनीतिक इनोवेशन लैब के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को सिस्टम डिजाइन, स्केलेबिलिटी और वास्तविक फिनटेक इकोसिस्टम में इंटीग्रेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका उद्देश्य अकादमिक ज्ञान और उद्योग की वास्तविक चुनौतियों के बीच की खाई को पाटना था। सरवजीत सिंह वीरक ने कहा कि फिनटेक का भविष्य केवल तकनीक से नहीं, बल्कि उसके बुद्धिमान उपयोग से तय होगा। यह हैकाथॉन युवा प्रतिभाओं को वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करने का एक मंच है।

लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब ने इंडस्ट्री-एकेडमिया-एच. आर. मीट 2026 का आयोजन किया

चंडीगढ़। लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब ने चंडीगढ़ में इंडस्ट्री-एकेडमिया-ल्फ मीट 2026 का आयोजन किया। इस इवेंट के दौरान, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम को लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, नॉर्दर्न रीजन, कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए। यह नॉर्थ इंडिया का पहला टङ्कव है जिसमें स्टूडेंट को सरकार से अप्रूव्ड अप्रेंटिसशिप के साथ डुअल डिग्री मिलेगी और उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी मिलेगा और स्टूडेंट कमाएगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा। यह पहल डिग्री प्रोग्राम के अंदर अप्रेंटिसशिप को जोड़कर एकेडमिक ट्रेनिंग और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच के गैप को कम करने के लिए डिजाइन की गई है। यह प्रोग्राम ल्फ प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के बीच अएउ्र के बारे में जागरूकता पैदा करने पर फोकस था ताकि इंडस्ट्री-एकेडमिया सहयोग को बढ़ाया जा सके और एम्प्लॉयमेंट में सुधार हो सके। इस इवेंट में श्री विवेक कुमार, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (इङ्कअळ), ठफ्, कानपुर मौजूद थे; उन्होंने द&अ सेशन में अपने विचार शेयर किए और सवालों के जवाब दिए। लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी के चांसलर निर्मल सिंह रियात ने इवेंट की तारीफ की और कहा कि हमें अच्छे नतीजों की उम्मीद है।

30 जून तक बाढ़ रोकथाम कार्य पूरे करने के आदेश, नहरी सिंचाई के दायरे को 78% से बढ़ाने पर जोर

बरिंदर कुमार गोयल द्वारा अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम, फ्लाइंग स्क्वॉड और तकनीक आधारित निगरानी के निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के जल संसाधन, भूमि एवं जल संरक्षण तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने तीन अलग-अलग विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सिंचाई परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाने और पूरे राज्य में बाढ़ रोकथाम कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में खनन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक व्यावसायिक खनन साइटों को चालू करने पर जोर दिया, ताकि लोगों को रेत-बजरी जैसे खनिज पदार्थों की आपूर्ति में सुधार हो और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। आधुनिक प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने निगरानी और नियंत्रण के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए।

जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री गोयल ने निर्देश दिया कि सभी बाढ़ रोकथाम कार्य 30 जून से पहले पूरे कर लिए जाएं, ताकि मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने अधिकारियों को नहरी पानी के तहत सिंचित क्षेत्र के वर्तमान 78 प्रतिशत दायरे को और बढ़ाने के लिए भी कहा ताकि भूजल पर निर्भरता कम की जा सके।

कैबिनेट मंत्री ने फसल सीजन को ध्यान में रखते हुए नहरी पानी के उपयोग से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सेम-प्रभावित भूमि के सुधार संबंधी पहल को सभी प्रभावित ज़िलों में विस्तार देने पर भी जोर दिया।

भूमि एवं जल संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए 5253 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिससे 1,61,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि को लाभ मिला है। राज्य सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि तीन बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिसमें गावों के तालाबों का उपयोग कर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई ढांचा तैयार करना, कंडी क्षेत्र में चेक डैम बनाकर मिट्टी के कटाव को रोकना, बाढ़ के प्रभाव को कम करना और भूजल रिचार्ज करना तथा फाजिल्का जिले के 29 गांवों में सेम-ग्रस्त भूमि की पुनर्बहाली के लिए विशेष परियोजना चलाना शामिल है।

उन्होंने बताया कि 250 से अधिक गांवों के तालाबों पर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे लगभग 10,500 एकड़ कृषि भूमि को लाभ मिल रहा है। सेम-प्रभावित क्षेत्रों के सुधार की परियोजना भी निरंतर प्रगति पर है और मई के अंत तक चार गांवों में इसके पूरा होने की उम्मीद है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खनन) श्रीमती जसप्रीत तलवाड़, प्रमुख सचिव (जल संसाधन) श्री कृष्ण कुमार, निदेशक (खनन) श्री अभिजीत कपलिश, मुख्य भूमि पाल श्री महिंदर सिंह सैनी, मुख्य अभियंता (खनन एवं ड्रेनेज) स. हरदीप सिंह मेंदीरत्ता, मुख्य अभियंता (कैनाल) श्री शेर सिंह, पीडब्ल्यूआरएमडीसी के प्रबंध निदेशक श्री मनोज बांसल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (लैंड एंड वॉटर कंजर्वेशन) श्री जी.एस. ढिल्लों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अशांत विश्व के लिए भारत-अफ्रीका साझेदारी बनेगी 'स्थिरता का स्तंभ'

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों का करेंगे सामना

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

वैश्विक स्तर पर बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितताओं के बीच, भारत और अफ्रीका ने अपनी पुरानी और प्रगाढ़ साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लिया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को आगामी 'भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन-4' के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करते हुए इसे एक 'अशांत और अनिश्चित दुनिया में स्थिरता और विश्वसनीयता का संदेश' बताया।

शिखर सम्मेलन 28 से 31 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न अफ्रीकी देशों के कई राजदूतों और राजनयिकों की उपस्थिति ने इस साझेदारी के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। वर्तमान समय में दुनिया कई तरह के संघर्षों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अन्य वैश्विक अस्थिरताओं का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि ऐसे समय में भारत और अफ्रीका की साझेदारी न केवल एक-दूसरे के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्थिरता का प्रतीक है। आगामी शिखर सम्मेलन की थीम 'स्थायी साझेदारी, साझा दृष्टिकोण' रखी गई है। सम्मेलन के लोगो में भारत और अफ्रीका के मानचित्रों को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाया गया है, जिस पर एक शेर की आकृति अंकित है। यह लोगो दोनों क्षेत्रों की शक्ति और उनके अंतर्संबंधों को दर्शाता है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत और अफ्रीका केवल विकास के साझेदार नहीं हैं, बल्कि वे मिलकर एक बेहतर और न्यायसंगत दुनिया को आकार देने की

क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा, ''हमारी यह साझेदारी कठिन समय में एकजुटता और भरोसे का एक मजबूत स्तंभ है। भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों की जड़ें काफी गहरी हैं, जो केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सभ्यतागत और ऐतिहासिक हैं। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में उस दौर को याद किया जब भारत और अफ्रीका दोनों ही उपनिवेशवाद के खिलाफ एक साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, ''संघर्ष, लचीलेपन और आकांक्षाओं का हमारा साझा इतिहास हमारी वर्तमान साझेदारी को परिभाषित करता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत ने जिस एकजुटता का प्रदर्शन किया था, उसने आज के समय में हमारे राजनयिक संबंधों को एक नैतिक और भावनात्मक आधार प्रदान किया है। इसी जुड़ाव को और अधिक मजबूत करने के लिए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी उपस्थिति को व्यापक रूप से बढ़ाया है। भारत ने अफ्रीका में 17 नए मिशन (दूतावास/कॉन्सुलेट) खोले हैं, जिससे अब महाद्वीप में भारतीय मिशनों की कुल संख्या 46 हो गई है। यह विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज अफ्रीका भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। यह न केवल राजनयिक मौजूदगी है, बल्कि यह दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान का प्रतिबिंब भी है।

भविष्य की ओर देखते हुए, भारत और अफ्रीका ने विकास के रोडमैप को आपस में जोड़ लिया है। भारत की 'विकसित भारत 2047' की परिकल्पना और अफ्रीका का 'एजेंडा 2063' एक-दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एजेंडे सतत विकास, समावेशी प्रगति और समृद्धि पर केंद्रित हैं। जयशंकर ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत लगातार वैश्विक व्यवस्था में अफ्रीका को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए पैरवी कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह में शामिल करना था। यह निर्णय वैश्विक शासन को दिशा देने में 'ग्लोबल साउथ' की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। विदेश मंत्री के अनुसार, आने वाले समय में वैश्विक निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में अफ्रीका की आवाज का महत्व और बढ़ेगा।

श्रीलंका वित्त मंत्रालय के डिजिटल सिस्टम में बड़ी सेंध, हैकरों ने उड़ाए 2.5 मिलियन डॉलर

एजेंसी (हि.स.)
कोलंबो

श्रीलंका के वित्त, योजना और आर्थिक विकास मंत्रालय ने देश की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवालिया निशान लगाते हुए बुधवार को पुष्टि की कि मंत्रालय के 'बा' संसाधन विभाग' के कंप्यूटर सिस्टम में साइबर हैकरों ने घुसपैठ की है।इस साइबर हमले के कारण विदेशी मुद्रा भुगतान से संबंधित एक बड़ी वित्तीय चोरी को अंजाम दिया गया है, जिससे सरकारी खजाने को 25 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.5 मिलियन डॉलर) का भारी नुकसान हुआ है।यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब श्रीलंका अपनी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए विदेशी कर्ज चुकाने की जटिल प्रक्रिया से गुजर रहा है। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, विभाग के सिस्टम में अनधिकृत पहुंच बनाकर हैकरों ने धन के प्रवाह को गलत दिशा में मोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला सितंबर 2025 में श्रीलंका पर बकाया 2.29 करोड़ डॉलर के ऋण भुगतान से जुड़ा है। एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत दिसंबर 2025 और 31 जनवरी 2026 के बीच इस ऋण का आंशिक भुगतान किया जाना

था। जांच में यह खुलासा हुआ है कि 25 लाख डॉलर की आंशिक राशि का भुगतान किसी अधिकृत विदेशी ऋणदाता के खाते में जाने के बजाय, हैकरों द्वारा नियंत्रित एक फर्जी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।सूत्रों के मुताबिक, हैकरों ने 'मैन-इन-द-मिडल' या इसी तरह की उन्नत साइबर तकनीकों का उपयोग किया होगा, जिससे मंत्रालय को लगा कि भुगतान सही जगह हो रहा है, जबकि पैसा सीधे अपराधियों के हाथों में चला गया।

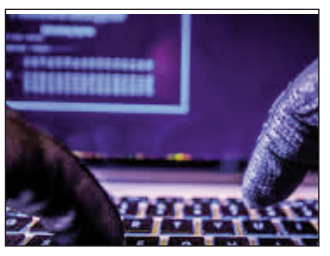

वित्त मंत्रालय ने इस चूक को स्वीकार करते हुए तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कंप्यूटर अपराध जांच प्रभाग , आपराधिक जांच विभाग और केंद्रीय बैंक की वित्तीय खुफिया इकाई को जांच में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक तकनीकी जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ खजाना अधिकारी शामिल हैं।यह समिति इस बात की जांच कर रही है कि क्या फर्जी ईमेल निर्देशों या सिस्टम में किसी अन्य तकनीकी खामी के कारण यह राशि डायवर्ट हुई। यह खबर सार्वजनिक होते ही श्रीलंका के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। विपक्ष ने इसे सरकारी लापरवाही का एक और उदाहरण बताते हुए संसद में जोरदार हंगामा किया है। वकीलों के एक समूह ने संसद के अध्यक्ष को औपचारिक पत्र लिखकर इस मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है। विपक्ष का तर्क है कि सार्वजनिक वित्त, संसद की सीधी जिम्मेदारी है और इस तरह की चोरी का होना सरकार की प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है। यह मुद्दा संसद की लोक लेखा समिति (सीओपीए) की कार्यवाही के दौरान भी उठाया गया, जहां विपक्षी सांसदों ने सरकार से पूछा कि इतनी बड़ी राशि के हस्तांतरण के दौरान 'टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' और 'वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल' क्यों विफल रहे इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकारी प्रवक्ता और मंत्री नलिंदा जयतिस्सा ने कहा, सरकार इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है।

बीडीएस छात्र की संदिग्ध मौत कन्नूर डेंटल कॉलेज में उग्र प्रदर्शन

एजेंसी (हि.स.)
कन्नूर (केरल)

केरल के कन्नूर जिले में एक निजी डेंटल कॉलेज में बीडीएस (इऊ) के प्रथम वर्ष के छात्र नितिन राज की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। इस घटना के विरोध में बृहस्पतिवार को यूथ लीग (वाईएल) के कार्यकताओं ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि एक 'संस्थागत हत्या' है, जिसमें कॉलेज के संकाय सदस्यों की भूमिका संदिग्ध है।

इस महीने की शुरूआत में, 10 अप्रैल को नितिन राज कॉलेज की इमारत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिर गए थे, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद से ही छात्र संगठन और परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को अंतराकांडी स्थित निजी डेंटल कॉलेज के बाहर का नजारा रणभूमि जैसा था। इंडियन

यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की युवा शाखा, यूथ लीग के कार्यकर्ता सुबह से ही कॉलेज के मुख्य द्वार पर एकत्र हो गए थे। कॉलेज प्रबंधन और कथित तौर पर जिम्मेदार संकाय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया और जबरन कॉलेज परिसर के अंदर घुस गए। मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प और धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि वे शिक्षक, जिन्होंने नितिन को प्रताड़ित किया, उन्हें तुरंत निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुनाफे में 6.6% की छलांग

नई दिल्ली। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए गुरुवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, जब सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के नतीजे घोषित किए। एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल के बीच बैंक ने 6.64 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,316 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 4,985 करोड़ रुपये था। यह नतीजे न केवल बैंक की परिचालन दक्षता को दशार्ते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और अनुशासित स्थिति में हैं। बैंक द्वारा शेयर बाजार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मुनाफा बनाए रखना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यूनियन बैंक के इन परिणामों का विश्लेषण करें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। जहां बैंक के मुनाफे में वृद्धि हुई है, वहीं इसकी शुद्ध ब्याज आय में मामूली गिरावट देखी गई है। तिमाही के दौरान मुख्य आय या शुद्ध ब्याज आय सालाना आधार पर 1.14 प्रतिशत घटकर 9,406 करोड़ रुपये रही।

सिंगापुर में एक्टिविस्ट पर सोशल मीडिया पोस्ट में सुधार का आदेश नहीं मानने का आरोप

एजेंसी (हि.स.)
सिंगापुर

भारतीय मूल की एक मृत्युदंड विरोधी कार्यकर्ता पर बृहस्पतिवार को सिंगापुर की एक अदालत में ऑनलाइन झूठी सूचनाओं और हेरफेर से सुरक्षा अधिनियम(पीओएफएमए) के तहत जारी सुधार निर्देश का पालन न करने का आरोप दर्ज किया गया है। चैनल न्यूज एशियाके अनुसार, अदालती दस्तावेजों में अन्नामलाई कोकिला पार्वती के रूप में सूचीबद्ध कोकिला अन्नामलाई पर अक्टूबर 2024 में सोशल मीडिया पर की गईं कुछ पोस्ट के संबंध में आरोप लगाए गए हैं।

ये पोस्ट एक व्यक्ति जिसे मृत्युदंड सुनाया गया है और उसके परिवार के अनुभवों के बारे में थीं। उन्होंने मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद अजवान बोहारी के बारे में पोस्ट किए थे।उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार मनमाने ढंग से फांसी की तारीख तय करती है

या उसे टालती है, और तस्करी के मामलों में कानूनी रूप से सबूत पेश करने की जिम्मेदारी नहीं उठाती। पीओएफएमए कार्यालय ने पांच अक्टूबर 2024 को उन्हें उन पोस्ट पर सुधार नोटिस लगाने का निर्देश जारी किया था। पीओएफएमए कार्यालय ने मंगलवार को कहा, आरोप है कि उन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया। सिंगापुर के कानून के तहत, पीओएफएमए आदेश का पालन न करने पर 12 महीने तक की कैद या 20,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुमार्ना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। अन्नामलाई को मई में मुकदमे से पहले की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होना है। खबरों के अनुसार, अन्नामलाई पर पहले दो अन्य महिलाओं के साथ एक अलग मामले में फलस्तीन समर्थक जुलूस को इस्ताना (राष्ट्रपति भवन) तक ले जाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अक्टूबर 2025 में उन्हें बरी कर दिया गया था।

वाशिंगटन में अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को कहा, आतंकी पनाहगाहों पर नकेल कसें

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

अमेरिकी राजधानी के सत्ता के केंद्र 'कैपिटल हिल' (अमेरिकी संसद भवन परिसर) में आयोजित एक डिजिटल प्रदर्शनी 'आतंकवाद की मानवीय कीमत' ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका की साझा प्रतिबद्धता को एक बार फिर मजबूती से दोहराया है। इस कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी सांसदों ने न केवल आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की, बल्कि पाकिस्तान पर भी कड़ा प्रहार किया। सांसदों ने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को अपनी जमीन पर पनाह देना बंद करना होगा।

अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने इस अवसर पर बेहद मुखर रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेर लिया। उन्होंने 2025 के पहलगाम

आतंकी हमले की पहली बरसी का उल्लेख करते हुए उन 26 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। शेरमैन ने कहा, द रेजिस्टेंस फोर्स (ळफ्फ्) के हमलावरों ने पीड़ितों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया। यह समूह लश्कर-ए-तैयबा से गहराई से जुड़ा है, जिसे पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह मिली हुई है। इस प्रदर्शनी में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों दलों के सांसदों ने शिरकत की, जो यह दशार्ता है कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिकी राजनीति में आम सहमति है। रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, माइकल बॉमगार्टनर, बिल हुइजेंगा, लीसा मैक्लेन, जेमी रास्किन और श्री थानेदार जैसे प्रभावशाली सांसदों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और अधिक वजन प्रदान किया। यह आयोजन ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान अमेरिका-ईरान के बीच जारी सात सप्ताह के युद्ध को समाप्त कराने की मध्यस्थता में खुद को एक 'शांतिदूत' के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, अमेरिकी सांसदों की टिप्पणियों ने पाकिस्तान के इस दावे के पीछे छिपे विरोधाभास को उजागर कर दिया। सांसदों का मानना है कि जो देश अपनी सरजमीं से संचालित लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को नकेल नहीं कस पा रहा है, उसकी शांतिदूत वाली छवि पर सवाल उठना लाजिमी है। प्रदर्शनी में 1993 के मुंबई बम विस्फोटों से लेकर 2008 के मुंबई हमलों और हालिया पहलगाम हमले तक का डिजिटल प्रदर्शन किया गया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दून घाटी में पारिस्थितिकी जोखिम पर सरकार से जवाब मांगा

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दून घाटी क्षेत्र में पर्यावरणीय और भूगर्भीय जोखिम को लेकर दायर एक अविलंब सुनवाई अर्जी पर राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद् रीनू पॉल द्वारा पूर्व में दायर की गई जनहित याचिका के तहत दायर इस अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अर्जी में देहरादून जिले के मसूरी डायवर्जन क्षेत्र और इससे सटे तलहटी क्षेत्रों में भूस्खलन की बढ़ती आशंका तथा अनियमित निर्माण गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त करते हुए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि इस स्थिति से मानव जीवन, संपत्ति और क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी के लिए खतरा पैदा हो गया है। पॉल द्वार दायर जनहित याचिका के अनुसार, संवेदनशील ढलानों पर निर्माण कार्य, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले भू-धंसाव और झड़ीपानी जैसे क्षेत्रों में जमीन में दरारों आदि से संभावित आपदाओं का जोखिम बढ़ गया है। याचिका में पारिस्थितिकी गिरावट और असुरक्षित शहरी विस्तार के दावों को प्रमाणित करने के लिए खबरों, उपग्रह छवियों, भू-टैग वाली तस्वीरों और आधिकारिक दस्तावेजों को आधार बनाया गया है।

अदालत ने स्वयंभू बाबा खरात को पांचवें मामले में छह मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

एजेंसी (हि.स.)
नासिक

नासिक की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को स्वयंभू 'बाबा' अशोक खरात को यौन उत्पीड़न और शोषण के पांचवें मामले में छह मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खरात को 18 मार्च को तब गिरफ्तार किया गया था जब 35 वर्षीय एक महिला ने सरकारवाड़ा थाने में उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। तब से उस पर कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और दैवीय शक्तियों और काले जादू के ज्ञान का दावा करके बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोप सामने आए हैं।

पुलिस के अनुसार, पांचवें मामले में खरात पर आरोप है कि उसने एक विवाहित महिला का यौन शोषण किया, जिसने पारिवारिक समस्याओं में मदद के लिए उससे संपर्क किया था। उसने महिला को यह भी चेतावनी दी थी कि यदि उसने इस शोषण के बारे में किसी को बताया तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने खरात के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। नासिक और अहिल्यानगर जिलों में उसके खिलाफ कम से कम 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से आठ यौन उत्पीड़न के हैं। एसआईटी ने 18 अप्रैल को पांचवें मामले में उसकी हिरासत मांगी थी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद एसआईटी ने उसे हिरासत में ले लिया और अगले दिन अदालत में पेश किया। अदालत ने खरात को 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से बृहस्पतिवार को अदालत की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई।

तेलंगाना आरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, यात्री परेशान

एजेंसी (हि.स.)
हैदराबाद

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी जारी रहने के कारण यात्रियों को निजी परिवहन पर निर्भर होना पड़ा। कर्मचारियों ने आरटीसी के सरकार में विलय सहित अपनी 32 मांगों के समर्थन में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आरटीसी ने जनता की सुविधा के लिए निजी तथा इलेक्ट्रिक बस चलाने की कोशिश की।

बस अड्डों पर पहुंचे यात्रियों को बस पकड़ने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने मीडिया से कहा कि बसों की अनुपलब्धता के कारण ऑटो सहित निजी वाहन भारी किराया वसूल रहे हैं। विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को समर्थन देते हुए सरकार से उनकी मांगें मानने को कहा। पूर्व बीआरएस विधायक मेथुकू आनंद ने विकाराबाद

जिले के तांडूर में प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आरटीसी सूत्रों के मुताबिक, हड़ताल के कारण 22 अप्रैल को केवल 25 से 30 प्रतिशत बस ही चलाई जा सकीं। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने करीब 65 लाख लोगों द्वारा आरटीसी बसों का रोजाना उपयोग किए जाने के मद्देनजर कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की। उन्होंने बीआरएस विधायक टी. हरीश राव पर हड़ताल के जरिए आरटीसी की खराब छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रभाकर ने कहा कि कुल 32 में से 29 मांगों पर सरकार का कोई विरोध नहीं है और आरटीसी का सरकार के साथ विलय तथा निगम के मान्यता प्राप्त संघों में चुनाव जैसी दो प्रमुख मांगों पर तकनीकी मुद्दे सुलझाने की जरूरत है।

समीक्षा

हिंद-प्रशांत में 'ज्वाइंटमैनशिप' का नया अध्याय

नौसेना प्रमुख ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए परिचालन तालमेल पर जोर दिया

एजेंसी (हि.स.)
श्री विजय पुरम

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के बीच समन्वय तथा पारस्परिक संचालन क्षमता के महत्व पर जोर दिया। एडमिरल त्रिपाठी दो दिवसीय दौरे पर अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) आए थे, जहां उन्होंने परिचालन तैयारियों की समीक्षा की और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त रूप से काम करने तथा बेहतर तालमेल मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि 21 से 22 अप्रैल तक इस दौरे के दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत की और उन्हें क्षेत्र में जारी परिचालन गतिविधियों तथा पहलों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि चचाओं का केंद्र परिचालन समन्वय को मजबूत करना, तैयारियों में सुधार करना और सेनाओं के बीच एकीकरण को गहरा करना रहा। द्वीपों के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि एएनसी क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, निगरानी क्षमता बढ़ाने और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, विशेषकर महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के निकट होने के कारण। उन्होंने वहां तैनात कर्मियों से भी बातचीत की और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में उनकी पेशेवर दक्षता, समर्पण और उच्च स्तर की परिचालन तत्परता की सराहना की।

इससे पहले जनवरी में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का दौरा किया था और भारतीय वायुसेना के कार निकोबार एयरबेस पर उन्नत रनवे का उद्घाटन किया था।

संक्षिप्त-समाचार

नाइजीरिया में चरमपंथियों का खूनी खेल: हमले में 11 लोगों की निर्मम हत्या, दो घायल

मैदुगुरी (नाइजीरिया)। इस्लामी चरमपंथियों ने पूर्वोत्तर नाइजीरिया के एक सुदूर गांव पर रात में हमला कर 11 लोगों की हत्या कर दी और दो अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में जारी हिंसा की ताजा घटना है जहां लंबे समय से जटिल सुरक्षा संकट बना हुआ है। बोर्नो प्रांत के सांबिसा जंगल की सीमा पर बसे पुबागु गांव में यह हमला मंगलवार देर रात हुआ। बोर्नो राज्य इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ नाइजीरिया की लंबी लड़ाई का केंद्र रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने इस हमले के लिए चरमपंथी संगठन बोको हरामको जिम्मेदार ठहराया। स्थानीय परिषद के अध्यक्ष मवाडा सैदू उबा ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह गांव पहले सुरक्षित स्थानों में माना जाता था। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने कहा, पुबागु हमारे परिषद क्षेत्र के उन स्थानों में से एक था, जहां कल तक कभी इस तरह का हमला नहीं हुआ था।उन्होंने बताया कि दोनों घायलों का पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

संयंत्र में रासायनिक स्राव से दो लोगों की मौत 19 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती: अधिकारी

वर्जिनिया। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्थित एक संयंत्र में रासायनिक स्राव के कारण दो लोगों की मौत हो गई जबकि 19 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कनावा काउंटी आयोग के आपातकालीन प्रबंधन निदेशक सीडब्ल्यू सिगमैन ने बताया कि यह स्राव इंस्टीट्यूट स्थित सिल्वर रिकवरी कंपनी कैटलिस्ट रिफाइनर्स संयंत्र में उस समय हुआ, जब कर्मचारी संयंत्र के कम से कम एक हिस्से को बंद करने की तैयारी कर रहे थे। सिगमैन ने बताया कि संयंत्र में नाइट्रिक एसिड और एक अन्य पदार्थ के बीच रासायनिक गैस की प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने बताया कि इस प्रतिक्रिया के कारण रसायनों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और वे तुरंत ही अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों में स्राव की घटना में मदद के लिए पहुंचे सात एम्बुलेंसकर्मी भी शामिल थे।

त्रिशूर पूरम पर्व से पहले अतिरिक्त विस्फोटक जमा करने के आरोप में मामला दर्ज

पलक्कड (केरल)। राजस्व विभाग ने प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम पर्व के लिए आतिशबाजी मुहैया कराने वाली एक पटाखा बनाने की इकाई पर छापेमारी की और यहां मुथलमदा में अनुमति से अधिक मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हाल में त्रिशूर में पटाखा बनाने वाली एक इकाई में विस्फोट से 14 लोगों की मौत हो जाने के बाद छापेमारी अभियान शुरू किया गया। चित्तूर के तहसीलदार के निदेर्शों पर कार्रवाई करते हुए कोल्लेनगोडे पुलिस ने इकाई के लाइसेंस धारक बिनॉय जैकब के खिलाफ मामला दर्ज किया। जैकब ने पर्व के तहत परमेकावु देवस्वओम के लिए आतिशबाजी का ठेका हासिल किया था। प्राथमिकी के अनुसार, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों ने मंगलवार को इकाई का निरीक्षण किया। प्राथमिकी में कहा गया है कि लाइसेंस के तहत निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में विस्फोटक और आतिशबाजी का भंडार पाए जाने पर तहसीलदार ने एक निषेध ज्ञापन जारी किया और पुलिस में एक शिकायत की, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात भारतीय न्याय संहिता और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पटाखा बनाने वाली इकाई में तिरुवमबडी देवस्वओम पर्व के लिए आतिशबाजी तैयार करते समय मंगलवार को विस्फोट हो गया था।

केपी एनर्जी: सीईआरसी से मिला अंतर-राज्यीय बिजली व्यापार लाइसेंस

नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केपी एनर्जी लिमिटेड को अंतर-राज्यीय बिजली व्यापार के लिए 'श्रेणी-१' का लाइसेंस प्रदान किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी अपनी आधिकारिक सूचना में इसे व्यापार विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस लाइसेंस के साथ, कंपनी अब राज्य की सीमाओं के पार बिजली का व्यापार करने के लिए पूरी तरह अधिकृत है। यह मंजूरी कंपनी को राष्ट्रीय बिजली बाजारों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न क्षेत्रों में मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति को समायोजित करने की क्षमता प्रदान करेगी। कंपनी ने इसे भारत के विकसित होते बिजली बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूती देने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर माना है।

एल्युमीनियम वायदा भाव में मामूली तेजी

नई दिल्ली। हाजिर बाजार में मजबूत रुख और सटोरियों द्वारा किए गए नए सौदों के कारण एल्युमीनियम के वायदा भाव में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार के दौरान कीमतों को सहारा मिला। मई अनुबंध का भाव 0.01 प्रतिशत (या पांच पैसे) की बढ़त के साथ 371.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गया है। इस सत्र के दौरान कुल 240 लॉट का व्यापार दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार, उपभोग करने वाले उद्योगों से निरंतर मांग और कारोबारियों द्वारा किए गए ताजा सौदों ने वायदा बाजार में एल्युमीनियम की कीमतों को सपोर्ट दिया है।

सीबीएसई की 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं 15 से 21 मई तक होंगी

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बृहस्पतिवार को 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया, जो 15 मई से 21 मई तक आयोजित होगी। सीबीएसई द्वारा जारी 'डेटशीट' के अनुसार, परीक्षा की शुरूआत 15 मई को गणित (स्टैंडर्ड और बेसिक) के पर्चे से होगी। इसके बाद 16 मई को अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव) और अंग्रेजी (लैंग्वेज एंड लिटरेचर) की परीक्षा होगी। विज्ञान विषय की परीक्षा 18 मई को आयोजित की जाएगी। 19 मई को भाषा और वैकल्पिक विषयों की परीक्षा निर्धारित की गयी है, जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती तथा कई विदेशी भाषाएं शामिल हैं। इसी दिन गृह विज्ञान और कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी होंगी।

दक्षिण अफ्रीका का दबदबा: भारत को नौ विकेट से रौंदकर सीरीज पर कब्जा

वोल्वार्ट के तूफानी शतक से ढहा भारतीय किला

एजेंसी (हि.स.)

जोहानिसबर्ग (हि.स.)।

- चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के बावजूद बेअसर रहे भारतीय गेंदबाज

दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग स्थित वांडरर्स स्टेडियम में एक बार फिर महिला क्रिकेट का एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे भारतीय प्रशंसक लंबे समय तक याद नहीं रखना चाहेंगे। पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। यह जीत न केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह श्रृंखला के बाकी बचे मैचों के लिए भी मेजबान टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है।

मैच के मुख्य आकर्षण कप्तान लौरा वोल्वार्ट रही, जिन्होंने 53 गेंदों में 115 रनों की आतिशी शतकीय पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। उनके साथ सुने लुस (42 गेंदों में नाबाद 64 रन) ने मिलकर पहले विकेट के लिए 183 रनों की अटूट साझेदारी की, जिसने भारत के विशाल स्कोर को भी बौना साबित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (66) और शेफाली वर्मा (64) के अर्धशतकों की मदद से चार विकेट पर 192 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। क्रिकेट के जानकारों का मानना था कि 190 से अधिक का स्कोर डिफेंड करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वांडरर्स की पिच पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जिस आक्रामकता का प्रदर्शन किया, उसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। भारत की शुरूआत अच्छी रही थी। शेफाली वर्मा ने एक बार फिर अपनी आक्रामक शैली दिखाई और स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 68 रनों की भागीदारी निभाई। पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 51 रन बनाकर भारत ने एक मजबूत नींव रखी थी। हालांकि, नौवें ओवर में मलाबा ने मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स को लगातार गेंदों पर आउट कर मैच में दक्षिण अफ्रीका की वापसी कराई। इसके बावजूद, शेफाली और हरमनप्रीत ने जिम्मेदारी संभाली और स्कोर को 192 तक पहुँचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने शुरूआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। वोल्वार्ट ने पहली ही गेंद से भारतीय तेज गेंदबाजों–रेणुका सिंह और काश्वी गौतम–पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उनके लिए यह दिन किसी सपने जैसा था, लेकिन भारतीय फील्डिंग ने इस सपने को हकीकत में बदलने में बड़ी भूमिका निभाई।

वोल्वार्ट को चौथे ओवर में 31 रन के निजी स्कोर पर स्मृति मंधाना ने जीवनदान दिया। इसके बाद 85 रन के स्कोर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उनका कैच टपकाया। टी20 क्रिकेट में एक सेट बल्लेबाज को दो बार जीवनदान देना किसी भी टीम के लिए आत्मघाती साबित होता है, और भारत के साथ भी यही हुआ। इन जीवनदानों का भरपूर फायदा उठाते हुए वोल्वार्ट ने अपनी पारी में 14 चौके और पांच गगनचुंबी छक्के जड़े। यह उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा शतक था, जिसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17 शतकों के साथ स्मृति मंधाना और मेग लैनिंग की बराबरी कर ली।

लखनऊ की हार के बाद ऋषभ पंत ने मानी हार, कहा- 'मेरे पास कोई जवाब नहीं है'

- पिच को पढ़ने में चूकी लखनऊ की टीम बल्लेबाजी पर उठ रहे सवाल

एजेंसी (हि.स.)

लखनऊ

लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को 40 रनों से करारी शिकस्त दी। इस हार के बाद लखनऊ के खेमे में मायूसी साफ देखी गई, खासकर टीम के कप्तान ऋषभ पंत के चेहरे पर। 160 रनों के अपेक्षाकृत छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम महज 119 रनों पर ही ढेर हो गई। यह हार न केवल टीम की अंक तालिका में स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि यह उनकी बल्लेबाजी इकाई की खामियों को भी उजागर कर गई है।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत काफी निराश नजर आए। जब उनसे बल्लेबाजी में खराब प्रदर्शन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। पंत ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उनके पास इस असफलता का कोई ठोस जवाब नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बल्लेबाजी ने हमें निराश किया है। हम एक टीम और एक समूह के रूप में इस परिणाम से काफी हताश हैं। पंत ने यह भी माना कि टीम पिच की स्थिति को सही ढंग से नहीं समझ पाई। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम को बाहरी जवाबों के बजाय अपनी कमियों को अंदर जाकर ढूंढना होगा। पंत ने कहा, आपको जवाब बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ढूंढने होंगे। बल्लेबाजी के दौरान हमें क्रीज पर थोड़ा और समय बिताना चाहिए था और स्थिति को समझना था। कोई बहाना नहीं है। मुझे भी अपनी पारी को गहराई तक ले जाना चाहिए था। एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि, पंत ने हार के बावजूद टीम के लिए कुछ सकारात्मक पहलू भी ढूंढे और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम में अभी भी सत्र में शानदार वापसी करने की पूरी क्षमता मौजूद है।

वहीं दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी खुश दिखे। उन्होंने मैच के बाद कहा कि उन्हें पिच की प्रकृति का अच्छी तरह अंदाजा था और गेंदबाजों ने उसी के अनुसार अपनी योजना का पालन किया। पराग ने विशेष रूप से अपने तेज गेंदबाजों की सराहना करते हुए कहा, हमें पता था कि पिच पर गेंद स्विंग करेगी। नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर ने जिस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, वह वाकई में शानदार थी। उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। राजस्थान की टीम में जीत के बाद माहौल काफी सकारात्मक है। पराग ने माना कि अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने का ही फल उन्हें मिला। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने न केवल विकेट चटकाए, बल्कि रन गति पर भी अंकुश लगाए रखा, जिससे लखनऊ के बल्लेबाज दबाव में आ गए और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे।

शारदुल ठाकुर और सिद्धेश लाड बने मुंबई के 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर'

एजेंसी (हि.स.)

मुंबई

मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के पुरस्कार समारोह में बुधवार को शारदुल ठाकुर और सिद्धेश लाड को क्रमशः 2024-25 और 2025-26 सत्रों के लिए 'साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर' चुना गया। दोनों खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ सीनियर क्रिकेटर के रूप में जस्टिस तेंदोलकर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान मुंबई के उन खिलाड़ियों और कोचों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की खिताबी सफलताओं में योगदान दिया।

युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे को इस साल दक्षिण अफ्रीका में भारत की अंडर-19 टीम को रिकॉर्ड छठा विश्व कप खिताब दिलाने के लिए सम्मानित किया गया। उनके साथ विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू को भी सम्मान मिला। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे को पिछले महीने टीम को रिकॉर्ड तीसरा टी20 विश्व कप जिताने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जेमिमा रोड्रिग्स, भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार और गेंदबाजी कोच आविष्कार साल्वी को पिछले वर्ष देश को पहला वनडे विश्व कप खिताब दिलाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अंडर-19 महिला विश्व कप विजेता टीम की सदस्य सानिका चालके को भी सम्मानित किया गया। एमसीए ने अपने बयान में कहा, 2024-25 सत्र में घरेलू क्रिकेट में मुंबई का दबदबा जारी रहा।

थॉमस कप में फिर इतिहास रचने को बेताब भारतीय पुरुष टीम

- उबर कप में महिलाओं की होगी अग्निपरीक्षा

एजेंसी (हि.स.)

होर्सेंस (डेनमार्क)

बैडमिंटन की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टीम चैंपियनशिप–'थॉमस और उबर कप' का बिगुल बज चुका है। डेनमार्क के होर्सेंस शहर में शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में भारत की निगाहें एक बार फिर बैडमिंटन के शीर्ष पर कब्जा करने की हैं। पुरुष वर्ग (थॉमस कप) में जहां भारतीय टीम अपने स्वर्णिम युग को दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है, वहीं महिला वर्ग (उबर कप) में भारतीय टीम युवाओं के दम पर एक नई लकीर खींचने के इरादे से कोर्ट पर उतरेगी।

वर्ष 2022 में भारत ने थॉमस कप जीतकर जो इतिहास रचा था, वह भारतीय बैडमिंटन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। अब 2026 के इस संस्करण में, भारतीय पुरुष टीम का मनोबल ऊंचा है। टीम में आयुष शेट्टी जैसे उभरते सितारों का समावेश और लक्ष्य सेन की शानदार फॉर्म इसे और अधिक घातक बनाती है। आयुष ने हालिया बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में फाइनल तक का सफर तय कर यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। भारत अपने अभियान की शुरूआत शुक्रवार को कनाडा के खिलाफ करेगा। इसके बाद भारतीय टीम सोमवार (27 अप्रैल) को ऑस्ट्रेलिया और बुधवार (29 अप्रैल) को चीन के खिलाफ अपना मुकाबला खेलेगी। चीन और भारत को इस ग्रुप से नॉकआउट में पहुंचने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पूर्व भारतीय कोच विमल कुमार ने टीम की संभावनाओं पर कहा, हमारे पास थॉमस कप में फिर से चैंपियन बनने का बेहतरीन मौका है। एकल वर्ग में आयुष और लक्ष्य की जोड़ी, और युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का अनुभव भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत है। सात्विक और चिराग, जो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, टीम के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं। अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा जोश का यह मिश्रण भारत को खिताब का मजबूत दावेदार बनाता है। उबर कप में भारतीय महिला टीम के लिए चुनौती काफी बड़ी है। भारतीय टीम को 'ग्रुप ऑफ डेथ' कहे जाने वाले ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें उनके साथ 16 बार की चैंपियन चीन, मेजबान डेनमार्क और यूक्रेन जैसी मजबूत टीमें शामिल हैं। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला शुक्रवार (24 अप्रैल) को डेनमार्क के खिलाफ खेलेगी, जिसके बाद शनिवार को यूक्रेन और सोमवार को चीन से भिड़ंत होगी।

इस टूर्नामेंट में भारत को स्टार जोड़ी त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की कमी खलेगी, जो चोट के कारण बाहर हैं। हालांकि, भारतीय टीम के पास युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तन्वी शर्मा (विश्व जूनियर चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता), देविका सिहाग (थाईलैंड ओपन सुपर 300 विजेता) और उन्नति हुडा जैसे नाम टीम को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। तनीशा क्रास्टो का अनुभव और प्रिया कोंजेंगबम व श्रुति मिश्रा जैसी युवा जोड़ियों पर टीम का दारोमदार होगा। पीवी सिंधु के नेतृत्व में महिला टीम के लिए यह टूर्नामेंट अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच है।

राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर को अनुशासनहीनता के लिए मिली सजा

एजेंसी (हि.स.)

लखनऊ

फोटोः हि.स.

राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर पर लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुमार्ना लगाया गया है। आईपीएल ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि इस 30 वर्षीय खिलाड़ी के खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है।

बयान के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज नांद्रे बर्गर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुमार्ना लगाया गया है और उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है। बर्गर को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो मैच में किसी अन्य खिलाड़ी से अपमानजनक या आक्रामक अंदाज वाली भाषा का उपयोग, प्रतिक्रिया या इशारा करने से संबंधित है। इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपराध स्वीकार कर लिया। आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन के मामलों में मैच रेफरी का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है। रॉयल्स ने इस मैच में 40 रन से जीत दर्ज की थी।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: सत्ता के गलियारों से गांव की चौपाल तक लोकतंत्र का सफर

पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 में पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भी इसी दिन मनाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली, जो देश के सबसे पुराने शासी संगठनों में से एक है, भारत में लगभग 6 लाख समुदायों को नियंत्रित करती है।

पंचायती राज की नींवः इतिहास और संघर्ष की दास्तान

पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय समाज। 'पंचायत' शब्द अपने आप में पूर्ण है–'पंच' यानी पांच और 'आयत' यानी सभा। यह वही पांच लोगों की सभा रही है, जिसने सदियों से गांव के विवाद सुलझाए और विकास का खाका खींचा। लेकिन, आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में इसे एक संवैधानिक पहचान दिलाने का सफर बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के बीजों को बोने का श्रेय लॉर्ड रिपन को दिया जाता है, जिन्होंने 1882 में स्थानीय संस्थाओं को पहला लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। स्वतंत्रता के बाद, महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी आई। 1957 में, बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य लक्ष्य प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। मेहता समिति की सिफारिशें मील का पत्थर साबित हुईं। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का सुझाव दिया जो गांव से लेकर जिले तक जुड़ी हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सुझाव का स्वागत किया और 2 अक्तूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ हुआ। इसके तुरंत बाद, आंध्र प्रदेश ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया।

त्रि-स्तरीय ढांचाः लोकतंत्र की सीढ़ियां

लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए बलवंतराय मेहता समिति ने जिस त्रि-स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था, वह आज भी हमारी व्यवस्था का आधार है। यह ढांचा न केवल प्रशासनिक सुविधा प्रदान करता है, बल्कि जनता को सीधे निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है। **ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतः** यह सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो सीधे तौर पर गांव के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और विवादों के निपटारे के लिए काम करती है। **ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितिः** यह मध्यवर्ती इकाई है जो ग्राम पंचायतों के कार्यों में समन्वय करती है और उन्हें संसाधनों से जोड़ती है। **जिला स्तर पर जिला परिषदः** यह सर्वोच्च इकाई है जो जिले भर के विकास कार्यों की निगरानी करती है और राज्य सरकार व पंचायतों के बीच एक सेतु का काम करती है। वर्ष 1992 का 73वां संविधान संशोधन इस व्यवस्था के लिए 'संजीवनी' बनकर आया। इस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे वे किसी भी राज्य सरकार की इच्छाशक्ति की मोहताज नहीं रहीं, बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता बन गईं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 भी स्पष्ट करता है कि राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि वे स्वशासन की इकाइयां बन सकें। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'स्थानीय सरकार' को राज्य सूची का विषय बनाया गया है, जो उन्हें अपना भविष्य तय करने की शक्ति देता है।

डिजिटल युग में पंचायतेंः चुनौतियां और नए आयाम

आज जब हम 2026 में खड़े हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था एक नए संक्रमण काल से गुजर रही है। जहां एक ओर इसे 'डिजिटल इंडिया' का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर कई पुरानी चुनौतियां आज भी बरकरार हैं। डिजिटल क्रांति ने गांवों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता ला दी है। ई-ग्राम स्वराज और स्वामित्व जैसी योजनाओं ने बजट के बंदरबांट पर रोक लगाने की कोशिश की है। अब गांव का विकास केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका पूरा ब्योरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ड्रोन मैपिंग के जरिए गांवों में जमीन के मालिकाना हक का निपटारा हो रहा है, जिससे गरीब किसान को अपनी भूमि पर कानूनी सुरक्षा मिल रही है। हालांकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तकनीक केवल एक माध्यम है। वास्तविक सशक्तिकरण तब होगा जब पंचायतों के पास अपने वित्तीय स्रोत होंगे। अधिकांश पंचायतें आज भी राज्य या केंद्र से आने वाली ग्रांट पर निर्भर हैं। 'सरपंच-पति' जैसी सामाजिक कुरीतियां अभी भी कुछ क्षेत्रों में महिला नेतृत्व को पीछे धकेल रही हैं, लेकिन उम्मीद की किरणें भी कम नहीं हैं। नई पीढ़ी की शिक्षित महिलाएं अब रबर स्टैंप बनकर रहने के बजाय, अपनी पंचायत का नेतृत्व पूरी सक्रियता से कर रही हैं।

ग्राम स्वराज का अधूरा सपना

महात्मा गांधी ने कहा था, भारत गांवों में बसता है। उनका 'ग्राम स्वराज' का सपना सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्वायत्त शासन था जहाँ हर गांव अपना निर्णय खुद ले सके। आज, 73वें संविधान संशोधन के अधिनियमन के दशकों बाद, हमें रुककर यह पूछने की जरूरत हैः क्या हम उस सपने के करीब पहुँचे हैं ? 24 अप्रैल 1993 को जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, तो इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिनिधि लोकतंत्र बना दिया। अचानक, लाखों की संख्या में जन-प्रतिनिधि–सरपंच, प्रधान और वार्ड सदस्य–चुने जाने लगे। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिला, जिससे ग्रामीण सत्ता के गलियारों में पहली बार चूड़ियों की खनक सुनाई दी। यह एक मूक क्रांति थी। एक महिला, जो कभी घर की चारदीवारी तक सीमित थी, अब वह पंचायत में बैठकर गांव की जल-निकासी, स्कूल की मरम्मत और आंगनवाड़ी के राशन का बजट तय कर रही थी। यह बदलाव छोटा नहीं था, लेकिन क्या यह पर्याप्त है ?

सत्ता का विकेंद्रीकरणः एक कठिन सफर

पंचायती राज का मूल विचार 'विकेंद्रीकरण' था। राज्य सरकारों को अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को सौंपना था। हालांकि, हकीकत के धरातल पर यह प्रक्रिया आज भी कछुआ चाल से चल रही है। कई राज्यों में पंचायती संस्थाएं आज भी राज्य सरकार के 'पॉकेट यूनिट' की तरह काम करती हैं। वित्तीय स्वायत्तता का अभाव इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है। अक्सर यह देखा जाता है कि पंचायतें अपने खर्चों के लिए राज्य या केंद्र की अनुदान राशि पर पूरी तरह निर्भर हैं। जब तक एक पंचायत अपना पैसा खुद नहीं कमाती (कर संग्रह, स्थानीय संसाधनों का दोहन), तब तक वह 'स्वायत्त' कैसे हो सकती है ? कई ग्राम पंचायतों में आज भी जमीनी स्तर पर टैक्स वसूली एक बड़ी चुनौती है। रिकॉर्ड रखने की पुरानी पद्धति और डिजिटल साक्षरता की कमी इसमें बड़ी बाधा है। जब तक पंचायतें वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी, वे केवल सरकारी योजनाओं को लागू करने वाली एक 'एजेंसी' बनकर रह जाएंगी, न कि 'स्वशासन की इकाई'।

सरपंच-पति और प्रतिनिधित्व का यक्ष प्रश्न

पंचायती राज व्यवस्था के साथ एक कड़वा सच भी जुड़ा है, जिसे अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में दबा दिया जाता है–'सरपंच-पति' कल्चर। आंकड़ों के अनुसार, महिलाएं चुनाव तो जीतती हैं, शपथ तो लेती हैं, लेकिन फाइलें उनके पति या पुरुष रिश्तेदार साइन करते हैं। इसे 'प्रॉक्सी रिप्रजेंटेशन' कहते हैं। यह व्यवस्था की एक ऐसी विफलता है जिसे केवल कानून से ठीक नहीं किया जा सकता। यह सामाजिक मानसिकता का मुद्दा है। हालांकि, पिछले एक दशक में इसमें बदलाव भी आए हैं। नई पीढ़ी की शिक्षित महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। वे सिर्फ रबर स्टैंप नहीं रहना चाहतीं। जब एक महिला सरपंच अपनी पंचायत को 'डिजिटल' करती है, जब वह सरकारी स्कूल में शौचालय बनवाने के लिए राज्य के अफसरों से भिड़ती है, तो वह केवल एक गांव का विकास नहीं कर रही होती, वह पितृसत्तात्मक जड़ों को हिला रही होती है।

डिजिटल इंडिया और 'ई-ग्राम स्वराज'

तकनीक ने इस व्यवस्था में एक नई उम्मीद की किरण जलाई है। 'ई-ग्राम स्वराज' और 'स्वामित्व' जैसी योजनाओं ने ग्राम पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी बनाने की कोशिश की है। पहले पंचायत के बजट और खर्चों का हिसाब-किताब केवल एक रफ रजिस्टर पर होता था, जिसमें हेरफेर करना आसान था। आज, सारा डाटा ऑनलाइन है। स्वामित्व योजना के माध्यम से गांवों में ड्रोन के जरिए मैपिंग की जा रही है, ताकि हर संपत्ति का मालिकाना हक तय हो सके। यह केवल एक तकनीकी काम नहीं है; यह गांवों के करोड़ों परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज देने का काम है। जब एक किसान के पास अपनी जमीन का डिजिटल कार्ड होता है, तो वह बैंक से लोन ले सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। यह 'ग्रामीण अर्थतंत्र' की नई नींव है।

अमृत काल की दहलीज पर पंचायतें

भारत का भविष्य 'विकसित भारत' की ओर बढ़ रहा है, और यह लक्ष्य बिना सशक्त पंचायतों के हासिल नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता का नारा तब तक खोखला है जब तक हमारा हर गांव अपनी बुनियादी जरूरतों–पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी–के लिए आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। हमें पंचायतों को सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं, बल्कि 'नवोन्मेष' का केंद्र बनाना होगा। जो पंचायतें पानी के संरक्षण में, प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने में या सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। राज्यों को 73वें संशोधन की भावना के अनुरूप, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बिना किसी आनाकानी के पंचायतों को हस्तांतरित करनी होंगी।

हमें पंचायती राज को सिर्फ एक 'व्यवस्था' नहीं, बल्कि 'आंदोलन' बनाना होग

24 अप्रैल का दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे से मजबूत होता है। पंचायती राज दिवस सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हर नागरिक के लिए एक चिंतन का दिन होना चाहिए। क्या मैंने अपने गांव की ग्राम सभा में भाग लिया ? क्या मैंने अपने सरपंच से अपने वार्ड के विकास का हिसाब मांगा ? लोकतंत्र कोई उपहार नहीं है जिसे हम हर पांच साल में वोट देकर घर बैठ जाएं। यह एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। यदि हम चाहते हैं कि भारत की आत्मा–जो गांवों में बसती है–वह सशक्त और आत्मनिर्भर बने, तो हमें पंचायती राज को सिर्फ एक 'व्यवस्था' नहीं, बल्कि 'आंदोलन' बनाना होगा। जब हर गांव की चौपाल में फैसले आपसी सहमति और पारदर्शिता से लिए जाएंगे, तब जाकर असली स्वराज की सुबह होगी।

हरियाणा में योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगासन के प्रचार-प्रसार एवं समग्र विकास के लिए गहन मंथन

हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉ जयदीप आर्य ने सेक्टर-3 स्थित आयोग कार्यालय में बोर्ड की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती भी उपस्थित रहे। बैठक में हरियाणा योग आयोग के अधिकारिक एवं गैर-अधिकारिक सदस्यों के साथ-साथ विशेष आमंत्रित सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राज्य में योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगासन के प्रचार-प्रसार एवं समग्र विकास के लिए गहन मंथन हुआ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में शिक्षा पाठ्यक्रम में योग को लागू करने हेतु शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी गयी एवं आगामी कार्यवाही हेतु चर्चा की गई। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक शीघ्र आयोजित की जानी प्रस्तावित की गयी, जिससे स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में योग पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित किया जा सके। शिक्षा विभाग के लगभग 25,000 पूर्व में प्रशिक्षित पीटीआई/डीपीई के लिए संबंधित विभाग द्वारा आगामी महीनों में विशेष योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तकनीकी सहयोग हरियाणा योग आयोग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

शिक्षा विभाग द्वारा एक एडवाइजरी जारी करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत प्रातःकालीन सभा के बाद 15 मिनट सामान्य योग गतिविधियां किया जाना अनिवार्य हो। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र जारी कर 15 मिनट का योग सत्र अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही, अंतर-विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के दौरान 10-15 मिनट योग सत्र एवं हरियाणा योग आयोग की डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित करने हेतु चर्चा हुई। राज्य के सभी योग क्लबों के लिए मंडल (कमिश्नरी) स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने पर चर्चा की गयी।

आयुष योग सहायकों के लिए मई माह में कुरुक्षेत्र में एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रस्ताव रखा गया। प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के पंजीकरण आरंभ करने को लेकर चर्चा हुई एवं सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में गत वितीय वर्ष में हुए आय-व्यय का ब्यौरा रखा गया, जिसकी उपस्थित सभी सदस्यों ने अनुमोदना की। साथ ही सभी को अवगत करवाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम राज्यभर में जिला, ब्लॉक एवं योग व्यायामशालाओं में हरियाणा योग आयोग एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे हैं।

बैठक के दौरान सरकारी बौद्धिक अक्षमता पुनर्वास संस्थान, चंडीगढ़ की टीम द्वारा आयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके परिसर में मार्च माह में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। बैठक में श्री रोशन लाल हरियाणा योग आयोग के उपाध्यक्ष, डॉ सुषमा नैन, उप- निदेशक, आयुष विभाग, डॉ राजकुमार, रजिस्ट्रार, हरियाणा योग आयोग, श्रीमती लक्ष्मी पंत, अतिरिक्त निदेशक (योग), खेल विभाग, हरियाणा योग आयोग के सदस्य डॉ मनीष कुकरेजा, डॉ मदन मानव, श्री नरेश कुमार, श्रीमती सुमेश्ता देवी, डॉ कुलदीप सिंह, डॉ पवन गुप्ता, श्री जयपाल शास्त्री, श्री पंकज कुमार के साथ-साथ सुश्री निधि, प्रोग्राम अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्री धूप सिंह, अधीक्षक, उच्चतर शिक्षा विभाग, डॉ अरविन्द, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, श्री अनिल कुमार, प्राचार्य जीआरआईआईडी, डॉ युधवीर, सचिव, एचवाईएसए, श्री अजय, अध्यक्ष, न्यूरोथेरपी सहित आयोग के कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक का समापन सभी सदस्यों के धन्यवाद ज्ञापन एवं शांति पाठ के साथ किया गया।

तीन दिवसीय शिविर में केंद्र एवं राज्य सामाजिक न्याय योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी पर होगा मंथन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब - विकसित भारत @2047 विषय पर 24 से 26 अप्रैल, 2026 तक चंडीगढ़ में राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन
- केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार करेंगे अध्यक्षता, राज्य मंत्रियों की रहेगी उपस्थिति
- पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया 24 अप्रैल, 2026 को चिंतन शिविर में करेंगे सहभागिता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 24 से 26 अप्रैल, 2026 तक चंडीगढ़ में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तीन दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करेगा। अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब - विकसित भारत @2047 विषय पर आधारित यह शिविर अमृत काल की परिकल्पना के अनुरूप समावेशी सशक्तिकरण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। इस चिंतन शिविर का उद्देश्य सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना, अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाना तथा वंचित वर्गों के समावेशी एवं सतत सशक्तिकरण के लिए एक कार्यात्मक रोडमैप तैयार करना है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार करेंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा एवं श्री रामदास अठावले भी उपस्थित रहेंगे। शिविर में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री एवं अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक, गुलाब चंद कटारिया, 24 अप्रैल, 2026 को चिंतन शिविर में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम की शुरूआत मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी से होगी। इस अवसर पर समावेश पोर्टल, NMBA 2.0 ऐप, सेतु ऐप तथा स्माइल ऐप सहित कई महत्वपूर्ण डिजिटल एवं नीतिगत पहलों का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही डिमेंशिया केयर होम्स के लिए न्यूनतम मानकों तथा भिक्षावृत्ति गृहों के मॉडल दिशानिर्देशों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। तीन दिवसीय इस चिंतन शिविर में विषयगत चचाएँ एवं समूह सत्र आयोजित किए जाएंगे। 25 अप्रैल को छात्रवृत्ति वितरण एवं शैक्षिक पहुंच, नशा मुक्त भारत अभियान, स्वच्छता कार्य में गरिमा एवं शून्य मृत्यु मिशन, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल तथा दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा। 26 अप्रैल को क्षेत्र आधारित सामाजिक-आर्थिक विकास, वंचित समुदायों की पहचान एवं समावेशन, ऋण सुविधा एवं वित्तीय सशक्तिकरण, तथा दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एवं प्रमाणन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

मनीमाजरा और सेक्टर-26 के बीच संपर्क सुदृढ़ करने के लिए सुखना चोए पर उच्च स्तरीय पुल को मंजूरी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सड़क संपर्क अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मनीमाजरा और सेक्टर-26 को जोड़ने के लिए सुखना चोए पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव, श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। इस परियोजना पर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी गई। वर्तमान में, आवागमन करने वाले लोगों को मौजूदा वेंटेड नीचा पुल पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो चंडीगढ़ और पंचकूला के बीच दैनिक यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस नीचा पुल की सीमित चौड़ाई के कारण पीक आवर्स के दौरान भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त, मानसून के दौरान सुखना चोए में जलस्तर बढ़ने से यह मार्ग अक्सर बंद हो जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं तथा आम जनता को असुविधा होती है। यह मार्ग सुखना झील, सेक्टर-17, पीजीआई, पंजाब विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल से हर मौसम में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे वर्तमान अवरोध समाप्त होंगे और यातायात सुचारु रूप से संचालित हो सकेगा। यह परियोजना यात्रा समय में कमी लाने, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने तथा चंडीगढ़ के शहरी सड़क नेटवर्क की समग्र दक्षता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, साथ ही बढ़ते यातायात दबाव को भी संभालेगी।

लगभग 16.63 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के अंतर्गत दोहरे चार-लेन मार्ग वाले उच्च स्तरीय पुल का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की भी व्यवस्था होगी। इस परियोजना पर कार्य जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावना है, जिसे प्रारंभ से 12 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पीजीअआई ने मरीजों की सुरक्षा और शोषण रोकने के लिए एक खास विजिलेंस टीम बनाई

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मरीजों की सुरक्षा को मजबूत करने और एक पारदर्शी, मरीज-केंद्रित माहौल पक्का करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, पीजीआई चंडीगढ़ ने इंस्टीट्यूट के परिसर के अंदर मरीजों और उनके साथ आए लोगों के शोषण को रोकने के लिए एक खास विजिलेंस टीम बनाई है। यह फैसला रोजाना आने वाले लगभग 35,000-40,000 मरीजों और उनके साथ आए लोगों की बहुत ज्यादा संख्या को देखते हुए लिया गया है। इतनी बड़ी संख्या से जुड़ी कमजोरियों को पहचानते हुए—खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और कम पढ़े-लिखे तबकों में—इंस्टीट्यूट ने ठगी, धोखा, दलाली और जबरन वसूली की घटनाओं को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ा दी है। कैंपस के अंदर किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ पीजीआई की सख़्त जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए, पीजीआई के डायरेक्टर प्रो. विवेक लाल ने कहा, एक ऐसे संस्थान में जहाँ रोजाना इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी यह पक्का करना है कि हर मरीज और उसके साथ आया व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित और सुरक्षित महसूस करे। इस विजिलेंस टीम का गठन किसी भी रूप में शोषण के प्रति हमारे जीरो-टॉलरेंस रवैये को दिखाता है। हम खास तौर पर कमजोर तबकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि पीजीआई में इलाज के लिए आने पर किसी को भी गुमराह न किया जाए या उसका फायदा न उठाया जाए। विजिलेंस टीम का गठन सक्षम अधिकारी की मंजूरी से किया गया है और यह तुरंत असर से काम करना शुरू कर देगी। इसमें टीम के मुखिया के तौर पर पीजीआई सिक्योरिटी से एक सिक्योरिटी ऑफि सर, और साथ ही पीजीआई सिक्योरिटी और पूर्व-सैनिक सिक्योरिटी से लिए गए पाँच सिक्योरिटी कर्मचारी शामिल हैं। यह टीम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (विजिलेंस) की देखरेख में काम करेगी। इसकी बनावट और काम करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताते हुए, डिप्टी डायरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन) श्री पंकज राय ने कहा, यह विजिलेंस सिस्टम बहुत सोच-समझकर बनाया गया है ताकि यह समझदारी, कुशलता और जवाबदेही के साथ काम कर सके। सादे कपड़ों में तैनाती और अचानक व खुफिया जानकारी पर आधारित जांच के जरिए, यह टीम गलत कामों की तुरंत पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का उद्घाटन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का सफलतापूर्वक उद्घाटन विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। यह पहल विद्यार्थियों के बीच डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल Global Youth Federtiof द्वारा संचालित है। इस परियोजना को State NSS के सहयोग से लागू किया गया।

यह अक लैब एक आधुनिक एवं अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है, जिससे विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यावहारिक रूप से समझ सकें और उसमें दक्षता प्राप्त कर सकें। इस पहल का उद्देश्य केवल तकनीक उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए सार्थक एवं गुणवत्तापूर्ण सीखने के अवसर सृजित करना भी है। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय की प्राचार्या रंल्लीं३ं उुँ१ के मार्गदर्शन में किया गया।

इस अवसर पर अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रयोगशालाएं विद्यार्थियों को नए कौशल विकसित करने, विश्लेषणात्मक सोच को मजबूत करने और बेहतर करियर अवसरों के लिए तैयार करने में सहायक होंगी। यह अक लैब विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगी, उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करेगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी तथा उन्हें तकनीक के वास्तविक जीवन में उपयोग को समझने में मदद करेगी।

इस अवसर पर निदेशक, ग्लोबल यूथ फेडरेशन ने सभी सहयोगियों एवं साझेदारों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को आधुनिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिल सके। कार्यक्रम का समापन सकारात्मक संदेश के साथ हुआ, जिसमें डिजिटल शिक्षा, नवाचार और युवा सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित किया गया। यह पहल दीर्घकालिक रूप से विद्यार्थियों को कुशल, आत्मविश्वासी और भविष्य के लिए तैयार बनाने में सहायक सिद्ध होगी तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

पोषण पखवाड़ा 2026: सामुदायिक उत्साह के साथ स्वस्थ भविष्य की ओर अभियान का समापन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पोषण पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत विभिन्न सर्कलों में स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु अनेक सार्थक एवं आकर्षक गतिविधियों का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान में लाभार्थियों, फील्ड स्टाफ एवं सुपरवाइजर्स की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसने मजबूत सामुदायिक सहयोग को दशार्या। कजहेड़ी में एएनएम एवं एलएचवी द्वारा शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वल्रठऊ) तथा टीकाकरण विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। यह सत्र आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं एवं निवारक देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बना। लाभार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वस्थ आदतों को अपनाने में रुचि दिखाई। सर्कल 52 में फैमिली प्ले टाइम गतिविधि हर्षोल्लास के साथ आयोजित की गई, जिसमें माताओं एवं बच्चों ने स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के माध्यम से खेल-आधारित गतिविधियों में भाग लिया। इस पहल ने माता-पिता एवं बच्चों के बीच संबंधों को मजबूत करने, खेल के माध्यम से सीखने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। मनीमाजरा क्षेत्र में 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य उत्तेजना विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अभिभावकों को बच्चों के जीवन के शुरूआती वर्षों में मानसिक एवं भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक उत्तेजना के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

संक्षिप्त-समाचार

अवलोकन गृह, चंडीगढ़ का निरीक्षण; बच्चों हेतु भोजन एवं स्वच्छता व्यवस्थाओं की समीक्षा

चंडीगढ़। अवलोकन गृह, चंडीगढ़ का निरीक्षण सुनिल कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान रसोईघर का विशेष रूप से अवलोकन किया गया, जहां बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जांच की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि बच्चों को पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अवलोकन गृह के शौचालयों एवं स्वच्छता व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। साफ-सफाई, रखरखाव तथा समुचित सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन किया गया, ताकि वहां निवासरत बच्चों के लिए स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

भारत-विभाजन - पुस्तक का विमोचन

पंचकूला। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के प्रांगण में डॉ. वेदप्रकाश नागपाल द्वारा लिखित पुस्तक, 'भारत-विभाजन : एक हकीकत, एक अफसाना था आज विधिवत विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री तरुण भण्डारी, राज सचिव, मुख्यमन्त्री हरियाणा एवं डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ अकादमी हॉल में इस ऐतिहासिक घटना, अगस्त 1947 की सच्चाई जानने के लिए भारी संख्या में प्रबुद्ध श्रोता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में लेखक के अतिरिक्त डॉ. चन्द्रत्रिखा, निदेशक उर्दू प्रकोष्ठ एवं डॉ. राधेश्याम शर्मा मुख्य वक्ता रहे। कार्यक्रम में किशोर कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। मंच संचालन एकता द्वारा किया गया।

राजकीय महाविद्यालय कालका में पृथ्वी दिवस मनाया गया

पंचकूला। राजकीय महाविद्यालय कालका की प्राचार्या डॉक्टर गीता सुखीजा के कुशल नेतृत्व में पृथ्वी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें सतत विकास के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। इको क्लब की संयोजक डॉक्टर नीरू ने जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और बढ़ते प्रदूषण जैसे प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर इंदु ने दैनिक जीवन में छोटे लेकिन सार्थक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जैसे पानी बचाना, प्लास्टिक का उपयोग न करना और अधिक पेड़ लगाना। कार्यक्रम के अंतर्गत पृथ्वी दिवस प्रतिज्ञा भी ग्रहण की गई जिसमें सभी विद्यार्थियों और इको क्लब के सदस्यों ने पर्यावरण की रक्षा करने, कचरा कम करने और पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने की शपथ ली। उन्होंने दूसरों में जागरूकता फैलाने और स्वच्छ एवं हरित भविष्य के निर्माण में योगदान देने का भी संकल्प लिया। कुल 62 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल करने में इको क्लब की संयोजक डॉक्टर नीरू, डॉक्टर इंदु, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर नवनीत नैंसी, डॉक्टर गुरप्रीत कौर और डॉक्टर चेतना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पृथ्वी दिवस की शपथ डॉक्टर बिंदु शर्मा द्वारा पढ़ी गई। कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि पृथ्वी की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है और सामूहिक प्रयासों से महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

नगर निगम आम चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन एक उम्मीदवार ने भरा नामांकन

पंचकूला। नगर निगम आम चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन आज एक उम्मीदवार ने वार्ड सदस्य के लिए नामांकन भरा। रिटर्निंग ऑफिसर सह एसडीएम कालका श्री संयम गर्ग ने बताया कि श्री राजेश कुमार ने वार्ड नंबर 10 से आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सह जिला सांख्यिकीय अधिकारी श्री सुनील जाखड को प्रस्तुत किया। श्री सयंम गर्ग ने बताया कि आज के नामांकन के उपरांत नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 5 हो गई है, जिनमें 3 पुरूष और 2 महिला उम्मीदवार शामिल है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 19 पिछड़ा वर्ग ए की महिलाओं के लिए, वार्ड नंबर 18 पिछड़ा वर्ग बी की महिलाओं के लिए, वार्ड नंबर 7 और 17 अनुसूचित जाति के लिए, वार्ड नंबर 16 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, वार्ड नंबर 1, 2, 11, और 15 सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए, तथा वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 और 20 सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए हैं। मेयर और वार्ड सदस्यों के लिए नामांकन पत्र 25 अप्रैल तक प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित स्थानों पर रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के पास जमा किए जा सकते हैं।

गुरुग्राम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का थापली नेचर कैंप सफलतापूर्वक सम्पन्न, प्रकृति संरक्षण और राष्ट्र निर्माण का लिया संकल्प

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

गुरुग्राम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय नेचर कैंप थापली में आज सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। इस विशेष शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति के निकट ले जाकर पर्यावरण, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों के महत्व तथा उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। तीन दिनों तक चले इस कैंप में विद्यार्थियों ने प्रकृति को बहुत करीब से देखा, समझा और उसके महत्व को आत्मसात किया।

कैंप के दौरान विद्यार्थियों ने पहाड़ों, जंगलों, जल स्रोतों, वनस्पतियों तथा स्थानीय जीव-जंतुओं का अवलोकन किया। विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को बताया गया कि किस प्रकार प्रकृति मानव जीवन का आधार है और वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण क्यों अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों ने प्राकृतिक वातावरण में रहकर अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व क्षमता तथा समूह भावना जैसे गुणों का भी विकास किया।

तीन दिनों तक विद्यार्थियों ने प्रातःकालीन प्रकृति भ्रमण, ट्रैकिंग, पर्यावरण संवाद तथा विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कैंप के दौरान विद्यार्थियों ने यह अनुभव किया कि आधुनिक जीवनशैली में प्रकृति से दूरी बढ़ती जा रही है, जबकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रकृति से जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। इस अनुभव ने विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया।

कैंप में विशेष रूप से युवा कल्याण समन्वयक नरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए देश प्रथम की भावना पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि युवा अपने कर्तव्यों को समझते हुए समाज, पर्यावरण और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाएं, तो भारत को विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आान किया कि वे केवल अपने व्यक्तिगत विकास तक सीमित न रहें, बल्कि समाज और राष्ट्रहित को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

नरेंद्र सिंह ने कहा कि देश प्रथम का अर्थ केवल देशभक्ति के नारे लगाना नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, सेवा भावना, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक सद्भाव को अपनाना भी है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा शक्ति यदि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, तो देश की हर चुनौती का समाधान संभव है। विद्यार्थियों ने उनके विचारों को गंभीरता से सुना और राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया।

कैंप के दौरान गुरुग्राम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने टछअ हॉस्टल का भी भ्रमण किया। इसी भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने वहां की व्यवस्थाओं को नजदीक से देखा और समझा कि हमारे जन प्रतिनिधियों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं । यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा।

विद्यार्थियों ने कहा कि इस तीन दिवसीय नेचर कैंप ने उन्हें पुस्तकीय ज्ञान से आगे बढ़कर जीवन का व्यावहारिक ज्ञान दिया है। प्रकृति के बीच बिताए गए समय ने उन्हें मानसिक शांति, नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच प्रदान की। साथ ही राष्ट्रहित, सामाजिक जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता के बारे में भी नई समझ विकसित हुई है। विश्वविद्यालय से आए फैकल्टी मेंबर नवीन एवं विपिन ने इस सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए इस प्रकार के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और प्रकृति आधारित कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कैंप के समापन अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र सेवा और समाज कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों ने आयोजकों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह शिविर उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रहेगा।